SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I brought it in December and then, I brought it on 15th February.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Anyway, it is for tomorrow. You may please include it in the List of Business for tomorrow. We will take it up tomorrow. Now, let us begin the Short Duration Discussion. It is only for two-and-a-half hours, and everybody has to adhere to the time allotted. After that, we will take up one Bill, as agreed in the morning. That is the position. Now, Shri Pramod Tiwari. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. N. BALAGOPAL (Kerala): Sir, I am on a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is that?

SHRI K. N. BALAGOPAL: I want a ruling from you. In the morning, there was an issue raised. We all came here and we were shouting slogans against the use of military for a private purpose...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That was over. Don't raise it again.

SHRI K. N. BALAGOPAL: Sir, I want a ruling from you as to whether a case, under the consideration of a Tribunal, can be considered a *sub judice* affair. Is it similar to a Court case? I want a ruling from the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. I will examine it. I am not a legal expert. So, I will look into the papers and come back to you. Now, Shri Pramod Tiwari.

SHORT DURATION DISCUSSION

Prevailing agrarian crisis in the country

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपका आभारी हूँ कि देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। सर, मैं शुरू तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि इस समय कृषि मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं और आपने चर्चा शुरू करा दी। ...**(व्यवधान)**...

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): प्रमोद तिवारी जी, कृषि राज्य मंत्री जी यहां हैं और कृषि मंत्री जी भी आ रहे हैं, वे on the way हैं। आप अपनी बात कहिए, उसको हम भी नोट कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। आपकी हर बात को नोट किया जा रहा है। लीजिए, कृषि मंत्री जी भी आ गए।

श्री प्रमोद तिवारी: सर, वैसे तो जब से यह सरकार वादा करके आई है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हर क्षेत्र में बुरे दिन की शुरुआत हो गई है। हर मोर्चे पर यह सरकार असफल हो गई है, लेकिन अगर मोदी सरकार के पिछले दो साल पर नजर डालें, तो इनसे सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है, तो वे दो हैं — एक, जो इस देश का अन्नदाता है — किसान और दूसरा

[श्री प्रमोद तिवारी]

4.00 P.M.

नौजवान है। आज का विषय चूंकि किसानों का है, इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार में अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है, तो वह किसान है। किसान को सबसे ज्यादा पीड़ा दी गई है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें, इस देश के हालात देखें, तो जितने वर्कर हिन्दुस्तान में हैं, अगर 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें, तो 54.6 परसेंट, जो करीब 55 परसेंट है, कृषि क्षेत्र से हैं और आज वही सेक्टर सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी और उपेक्षित है।

[उपसभाध्यक्ष **(श्री सुखेन्दु शेखर राय)** *पीठासीन हुए*]

सर, मैं आपसे एक छोटी-सी बात कहना चाहता हूँ, जो इस बात की ओर इशारा करेगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यूपीए सरकार के समय जो ग्रोथ रेट था और एनडीए सरकार के समय में ग्रोथ का जो रेट है, उसमें 0.2 परसेंट की कमी आई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी इस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर की उपेक्षा हुई है। आप एनडीए सरकार के नेतृत्व में पीछे गए हैं। यह मैं आपसे 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूँ।

आज हालात यह है कि 17 राज्यों में 20 हजार प्रति वर्ष के हिसाब से एक किसान के परिवार की इनकम है। अगर हम अंदाजा लगाएँ तो सिर्फ 1,666 रुपये प्रति माह किसान को मिल रहा है।* अगर आप देखें, तो इस सरकार के कार्यकाल में वे काले दिन भी आए हैं, जब एक-एक दिन में 52 किसानों की मौत हुई है, आत्महत्या हुई है, उन्होंने जीवन से ऊबकर आत्महत्या की है। सबसे ज्यादा दुखद पहलू यह है कि बुंदेलखंड में और देश के कई हिस्सों में आज किसान अपनी फसल बेचकर नहीं जी रहा है, बल्कि वह अपने शरीर का खून बेचकर अपने परिवार की जीविका चला रहा है। यह मोदी सरकार के कार्यकाल का दुखद सच है। अगर आप इस सरकार की बानगी देखें, तो यह जानकारी मैं कहीं और से नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मोहनभाई कुंदिरया जी, जो कि राज्य मंत्री हैं, इन्होंने खुद लिखित जवाब में कहा है कि 2015 में 10 राज्यों में 16 से 90 मौतें हुई हैं। यह आपका लिखित जवाब है। ये जो मौतें हुई हैं, आप अंदाजा लगा लें कि वहां कौन सी सरकारें हैं। महाराष्ट्र में 725 मौतें हुई हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय कायम है। पंजाब में 449 मौतें हुई हैं। वहां भी आप ही की सरकार है। यह आँकड़ा तेलंगाना में 342, कर्णाटक में सिर्फ 107 और आंध्र प्रदेश में 58 है। यह लिखित आंसर है। अगर हम 2016 के आँकड़े देखें तो अभी तक सिर्फ 57 मौतें हुई हैं, यह मोदी सरकार की किसानों के क्षेत्र में उपलब्धि है।

अगर हम इस बात का तुलनात्मक अध्ययन करें कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं, तो पाएँगे कि ये इसलिए हो रही हैं कि 1970 में 76 रुपये एमएसपी, यानी समर्थन मूल्य था, जो किसानों को जीवित रहने के लिए दिया जाता है। आज 2015 में वह 1,450 रुपये है। अगर आप देखें, तो इसमें 19 गुना बढ़ोतरी हुई है। जिस समाज के 54 फीसदी लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, वहां पिछले कुछ सालों में आपने 19 गुना बढ़ाया है। कर्मचारी लोग भी समाज में ही हैं, उनकी तनख्वाह में 150 गुना वृद्धि हुई है, जबकि किसानों की सिर्फ 19 गुना वृद्धि हुई है। शिक्षकों और प्रोफेसरों की

---

* Expunged as ordered by the Chair.

तनख्वाहों में 170 गुना वृद्धि हुई है, किसानों की सिर्फ 19 गुना हुई है। स्किल्ड टीचर्स की तनख्वाह में 320 गुना वृद्धि हुई है, पर किसानों की सिर्फ 19 गुना हुई है। अगर हम टॉप एग्जिक्यूटिव की बात करें, जो इस राज में फल-फूल रहे हैं, तो उनकी तनख्वाह, उनकी इनकम 1,000 गुना ज्यादा बढ़ी है और किसानों की सिर्फ 19 गुना बढ़ी है। अगर हम 10 गुना को 100 गुना भी बताएँ, तो इस समय उनका समर्थन मूल्य 7,600 रुपये होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वह 19 गुना बढ़ा है, इसलिए अभी वह 1,450 रुपये है। हम उतना भी नहीं कहते, आज अगर वह उसी अनुपात में बढ़ा होता, तो गेहूँ का समर्थन मूल्य 7,600 रुपये होना चाहिए था।

अगर मैं इनका तुलनात्मक अध्ययन करूँ, तो वर्ष 2013-14 और 2014-15 की तुलना में वर्ष 2016 में गिरावट आई है। कृषि के हर क्षेत्र में गिरावट आई है, पर ये* में माहिर हैं, ये* में माहिर हैं, ये* में माहिर हैं। इन्होंने कह दिया कि बजट में जो ग्रोथ है, उसे पढ़कर सुना दिया कि वह बहुत है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ और इस सच्चाई को जानने के बाद आपको लगेगा कि किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा है। इन्होंने यह किया है कि जो ग्रोथ है, वह सब्सिडी के क्षेत्र में है और वह इसलिए है कि जब वित्त मंत्रालय देता था, उसे इन्होंने कृषि मंत्रालय में जोड़ दिया, तो कृषि क्षेत्र का बढ़ गया। इससे ज्यादा बाजीगरी और धोखा किसानों के साथ कुछ नहीं हो सकता था कि पहले आप वित्त विभाग से देते थे, वित्त मंत्रालय से देते थे, अब आपने उसको लाकर कृषि विभाग को देने के लिए कह दिया, तो ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन सच्चाई नहीं। अगर बहुत बड़ा देखें, तो 0.17 से 0.19 परसेंट हुआ है, जो .02 परसेंट है। कुल मिलाकर देखें, तो यह बहुत दुखद है। यह बताने वाला है कि मोदी सरकार में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है? ...**(व्यवधान)**... केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद की बात करें, तो इन्होंने 2,438 करोड़ से 2,340 करोड़ पर पहुंचा दिया है, यानी यह कम हुआ है। जो इनपुट किसान लगाता है, उसको आपने कम किया है- लागत नहीं, उसने जो पैदा किया है, उत्पादन किया है।

एक बड़ा भारी क्षेत्र है, कृषि राज्य मंत्री जी वहां से आते हैं, वह क्षेत्र गन्ने का है। एक ही कैश क्रॉप किसानों के लिए है और उसकी हालत यह है कि आज किसान का गन्ना खेतों में जलाया जा रहा है। उसे गन्ने का उचित दाम नहीं मिल रहा है, किसानों की बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार की मांग के बावजूद वहां पर मदद नहीं की जा रही है। हमारे दूसरे गैर-भाजपाई राज्य हैं, वहां पर भी आप किसानों की मदद नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार किस बात के लिए है? आपकी सरकार इसीलिए तो है कि अगर कोई दैवीय आपदा हो तो आप मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। बाढ़ आती है, आपकी मदद नहीं पहुंचती है, केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं पहुंचती है, आपका आकलन ही चलता रहता है, मौतें होती रहती हैं, आपका आकलन ही चलता रहता है, आप मदद नहीं करते। सूखा पड़ता है, दो साल का पैसा उत्तर प्रदेश को नहीं मिला है, तब का पैसा अब तक नहीं बंटा है। ओले गिरे, मैं यह नहीं कहूंगा कि जब से आपकी सरकार बनी है, जिस दिन से आप सत्ता में आए हैं — जब पानी बरसना चाहिए, तो सूखा पड़ जाता है और जब सूखा पड़ना चाहिए, तो बाढ़ आ जाती है, अगर फसल पक कर तैयार हो जाती है, तो ओले पड़ जाते हैं। कृषि मंत्री जी, आप बिहार के रहने वाले हैं। आप कलराज मिश्र जी से बनारस में जाकर अपनी सरकार की कुंडली दिखवाइए। ...**(समय की घंटी)**...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): आपकी सरकार के समय में वर्ष 2009-10 में सबसे बड़ा सूखा 2,000 गांवों में पड़ा था।

श्री प्रमोद तिवारी: माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाइए। आपको बोलने का मौका मिलेगा। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि जिस दिन से आपकी सरकार के कदम पड़े हैं, दो साल पूरे हो गए हैं और सूखा, सूखा और सूखा ही है। जब जरूरत होती है, तब पानी नहीं बरसता है। मैं परसों उत्तर प्रदेश में था। वहां पर भारी बारिश हुई है और फसल जमीन पर लेट गई है, अब उसके उठने की गुंजाइश नहीं है। कहा जाता है कि अगर राजा परोपकारी हो, तो जनता सुखी रहती है और अगर राजा का कुछ पाप हो, तो जनता को भुगतना पड़ता है। आपका पाप इस देश की जनता भुगत रही है। केंद्र सरकार का रुख बहुत पीड़ादायक और दुखद है। उत्तर प्रदेश ने जितना धन मांगा था, उतना धन उसे आज तक नहीं दिया गया है। बहुत सी महंगाई तो आपने बढ़ाई है, आपके साथियों ने बढ़ाई है। यह बताइए कि जब किसान की फसल होगी, तो उसकी ढुलाई होगी और 16 परसेंट आपने रेल का माल भाड़ा बढ़ा दिया। आपने किसान की कमर और तोड़ दी। यहां पर पेट्रोलियम मंत्री जी बैठे हुए हैं — 140 डालर प्रति बैरल, 130 डालर प्रति बैरल, 120 डालर प्रति बैरल खरीद कर यूपीए सरकार में 60-65 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल बेचा गया। आज 25 डालर प्रति बैरल खरीद कर आप फिर 60 रुपये प्रति लीटर में बेच रहे हैं। ये बीच वाले पैसे कौन बिचौलिया खा रहा है? अगर आप डीजल को सस्ता कर दें, तो किसान की सिंचाई हो जाएगी, क्योंकि पम्पिंग सेट डीजल से चलता है। ढुलाई करने के लिए ट्रेक्टर में डीजल लगता है, लेकिन आप जानबूझकर किसान को घटे मूल्य का फायदा नहीं दे रहे हैं। किसान को जो डीजल खरीदना पड़ता है, वह महंगा हो रहा है। किसान जो सामान बेचता है, वह सस्ता हो रहा है।

सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आई है, यह किसानों की दुश्मन नम्बर एक है। इसने हालात ऐसे कर दिए हैं कि किसान इनके राज में जीना नहीं चाहता है, वह मरना चाहता है। इससे ज्यादा शर्मनाक, दुखद और पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता है।

श्री भुपेंद्र यादव (राजस्थान): सम्मानीय उपसभाध्यक्ष महोदय, लगातार इस सदन में, हर सत्र में कृषि क्षेत्र में जो संकट रहते हैं, उसके विषय में चर्चा होती है। जिस समय हमारे देश को आज़ादी मिली, उसके मुकाबले में 67 सालों में हमने गावों की स्थिति ऐसी की कि कृषि पर कार्यबल अधिक होता चला गया और कृषि का जो परम्परागत विकास है, वह केवल फसल उत्पादन नहीं था, फसल उत्पादन के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं को देना, गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, फसल के साथ वेल्यू एडिशन करना और उसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र की उस आर्थिक संरचना में आने वाले जो भी भूमिहीन किसान से लेकर, कमजोर वर्ग से लेकर जो भी लोग हैं, उन सब के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना। लेकिन दुर्भाग्य से देश में 67 सालों में जो योजनाएं बनीं, उनमें इस विषय का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। अभी प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे और पिछले दो साल के आंकड़े देकर के वे कृषि क्षेत्र के बारे में बता रहे थे। अभी जब एक प्रश्न माननीय कृषि मंत्री जी से पूछा गया कि 2005-06 से लेकर 2012-13 का समय जब यूपीए के कार्यकाल का समय था, उस समय में खेती योग्य भूमि बढ़ी अथवा उसमें कमी हुई? सच बात तो यह है कि यूपीए के कार्यकाल में जो सदन में उत्तर रखा गया, 2005-06 में देश में 1,82,686 स्कवेयर हेक्टेयर खेती योग्य भूमि थी, जो यूपीए की

सरकार की नीतियों के कारण घट करके 2012-13 में 1,81,950 स्क्वेयर हेक्टेयर रह गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण सड़क है, इसका कारण बढ़ता हुआ शहरीकरण है। लेकिन अगर राज्यवार इसका विश्लेषण किया जाए, तो मुख्य रूप से जिन राज्यों में कमी हुई, वह कर्णाटक, राजस्थान और तमिलनाडु में हुई। कमी होने का जो कारण है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लगातार इन प्रदेशों में जो सूखा पड़ा है, मौसम की जो मार पड़ी है उसका हम कोई समुचित उपाय नहीं कर पाए। मैं तो माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र की इन समस्याओं को समझते हुए, जहां पर लगातार सूखा पड़ता है, जहां पर लगातार किसान अपनी खेती में मौसम की अनिश्चितता के कारण बार-बार नुकसान को झेलने का काम करता है, वहां पर इन्होंने "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" ला कर पहले जो भी योजनाएं चल रही थीं भारत में कृषि योजनाओं को लेकर, और जो खाद्यान्न सुरक्षा मिशन को लेकर के, हरित क्रातिं को लेकर के सतत कृषि मिशन को लेकर जितने प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे, उनको समायोजित करके हमारे देश की कृषि को बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारी वर्तमान सरकार के आने के बाद, कृषि क्षेत्र में किसान सभी तरीके से अपनी भूमि की उर्वरता को पहचान सके, इसके लिए सरकार के द्वारा "मृदा स्वास्थ्य योजना", "सॉयल हैल्थ कार्ड" की योजना शुरू की गई। जिस प्रकार से आज भी हमारी पर्यात भूमि अभी कृषि के सिंचन से युक्त नहीं है, देश में एक महत्वाकांक्षी "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" को शुरू किया गया, किसानों की इन्कम को बढ़ाने के लिए, निश्चितता को समाप्त करने के लिए "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" को शुरू किया गया। लेकिन इन योजनाओं का विस्तार करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि कृषि क्षेत्र का जो भी विकास सरकार कर रही है, आजादी के 60 साल से जिस प्रकार का विकास हुआ है, विकास तो हुआ लेकिन टिकाऊ विकास नहीं हुआ है। हर विकास के माध्यम को जिसको पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है, विकास को केवल इंजीनियरों और ठेकेदारों के निर्माण कार्यों तक ही सीमित रख दिया है। विकास कार्य केवल इंजीनियर्स और ठेकेदारों के द्वारा निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। विकास का अर्थ है कि समग्रता के आधार पर विकास होना चाहिए। हम केवल उत्पादन में वृद्धि नहीं देखें, हम इस बात को भी देखने का प्रयास करें कि जब हम विकास में जी.डी.पी. को देखते हैं तो वह केवल उत्पादन में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, वह समाज के, कुल मिलाकर जो खुशी के मानक हैं, उन खुशी के मानकों में वृद्धि होनी चाहिए।

समाज के जीवन स्तर में केवल उत्पादन के आधार पर नहीं, बराबरी के अवसर, भूमिहीन किसान के लिए सुविधा, रोजगार के अवसर, skill development के अवसर, विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग, अपनी खेती की जमीन के हिसाब से Soil Health Card के आधार पर विकास करना और खेती के साथ-साथ पशुपालन का भी विकास होना, खेती के साथ-साथ बागवानी का विकास होना और खेत को मार्केट से जोड़कर खेत का मार्केट पर अधिकार करने का प्रयास करना, यह सरकार को करना चाहिए। पूर्व में जब एनडीए की सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आई थी, तब किसान के पशुओं को खरीदने के लिए, विपणन करने के लिए नए कानून का प्रावधान किया गया था। आज भी जो सबसे बड़ी समस्या है कि जब एक बार सूखा पड़ता है या अकाल पड़ता है या बेमौसम की बारिश होती है, तो कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा संकट क्या है? कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा संकट इस बात का है कि अगर एक फसल बरबाद हो जाती है, तो किसान का परिवार दो साल, तीन साल पीछे हो जाता है। इसके लिए फसल बीमा योजना

[श्री भुपेंद्र यादव]

है। क्योंकि छः महीने बाद जो उसका पैसा आना होता है, उसके पास नकदी कमाने का कहीं और अवसर नहीं होता है। जिन जगहों पर दुर्भाग्य से किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, उन आत्महत्याओं का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम केवल कृषि की नकदी फसलों के साथ-साथ पशुपालन की, फल उत्पादन की, सब्जियों के उत्पादन की, जब हम ऐसी व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास करें कि जिस व्यवस्था के माध्यम से खेती की निर्भरता केवल नकदी फसलों के उत्पादन नहीं, अपितु उसके सहायक विषयों के उत्पादन के लिए हम आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि माननीय कृषि मंत्री के द्वारा बागवानी मिशन का जो विशेष प्रयास किया जा रहा है, हरित क्रांति योजना का, कृषि विकास योजना का, इन सब में नीचे के स्तर पर यदि हम किसान की फसलों का value addition अगर ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे, पंचायत स्तर पर value addition करेंगे, तो कम से कम जो भूमिहीन किसान हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अपने उद्यम के माध्यम से, छोटी-छोटी जगहों के माध्यम से उनको भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। अभी इस चर्चा के बाद सरकार के द्वारा एक लम्बे समय से जो इस देश के नदी मार्ग हैं, उनका एक विधेयक भी लाया जा रहा है। अभी तक तो देश में केवल पांच राष्ट्रीय राजमार्गों को नदी जल मार्ग बनाया गया है। सरकार ने अपनी दूरदृष्टि से जो विषय बहुत लम्बे समय से पैंडिंग पड़ा था, 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना तय किया है। मेरा यह मानना है कि ये जितने भी जलमार्ग होगें, ये हमारे किसानों से होते हुए गुजरेंगे। अगर हम इसको अपने किसान और खेती के विकास के साथ जोड़ेंगे, तो हम इसका उपयोग करेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ जो नहरी योजनाएं हैं, उन नहरी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से अगर पूरा करने का काम किया जाएगा, तो कम से कम हम सूखे की समस्या का समाधान कर सकेंगे। इसलिए इस देश में लगातार गन्ना किसान भी संकट में है, उनके समर्थन मूल्य की बात भी की जा रही है। सरकार ने दालों के मूल्य को बढ़ाने का पहली बार प्रयास किया है। सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि उसने दालों का भी समर्थन मूल्य घोषित किया है। हमें उन सब फसलों, जो देश के दैनिक जीवन में आती हैं, उनके समर्थन मूल्य को देकर किसान को उसके उचित परिश्रम का मूल्य देना होगा। हमारे देश में लगातार जो कृषि नीति अपनाई गई, उस कृषि नीति के कारण अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो इस बात का हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन काफी ज्यादा बढ़ा है। पिछले कम से कम दस सालों के अंदर 'मनरेगा' से लेकर जो सारी योजनाएं लेकर आए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार का पलायन पूरे देश में हुआ है, वह एक तरीके से शोचनीय विषय है। ग्रामीण क्षेत्र से पलायन किस प्रकार से रुके और इसके लिए सरकार ने आधारभूत संरचना खड़ा करने का काम किया है और जो 'प्रधान मंत्री सड़क योजना' और 'प्रधान मंत्री सिंचाई योजना' जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को शुरू किया है, उन परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को हम किस प्रकार से रोक सकें और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और खेती तथा किसानी का विचार करते समय हम केवल भूमि वाले किसान नहीं, भूमिहीन किसानों का भी विचार करें। हम केवल उत्पादन में वृद्धि नहीं, गांव के समग्र विकास की कल्पना का विचार करें। हम कम से कम कृषि मंत्रालय का एक खुशी सूचकांक का एक audit भी करवाएं कि आखिर खेती के विकास के कारण कितने ग्रामीण क्षेत्रों में हम खुशियों को बढ़ा सके हैं। लोगों के दैनन्दिन जीवन में बढ़ा सके हैं, गांव में सामाजिक भाई चारे को बढ़ा सके हैं, किस प्रकार से गांव में रोजगार के अवसर देकर बेरोजगारों के मन में हमेशा जो आशंकाओं के विषय रहते हैं, उनको कम कर सके हैं। एक और विषय, जो

कृषि क्षेत्र के विकास के लिए है, वह यह है कि हमारे देश में 250 से ज्यादा जैव विविधता के क्षेत्र हैं। यदि बीज उत्पादन की दृष्टि से देखें तो आज उत्तराखंड में राजमा की अनेक किस्म के बीज हैं, यदि चावल को देखें तो छत्तीसगढ़ में चावल की अनेक प्रकार की किस्में होती हैं, यदि बिहार को देखेंगे तो हाजीपुर जिले में कम से कम दस तरह के केलों की फसलें एवं प्रजातियां हैं। जहां से माननीय कृषि मंत्री जी आते हैं, वहां का ज़र्दा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यह जो देश की जैव विविधता है, इस जैव विविधता में यदि हम देश में एक तरह का बीज लाएंगे, तो इससे सबसे बड़ा खतरा है। मैं सूखे के साथ-साथ बीजों के संबंध में कहूंगा कि हमारे जो देशी बीज हैं, उन देशी बीजों को हम कैसे बचाकर रखें, अपने देश की जैव विविधता को कैसे बचाकर रखें, इसका उपाय सोचें। जो मौसम का संकट है और जो फसली संकट है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम खेती में एकदम से नए बीज और नई तकनीक लाते हैं। उसमें जो स्थानीय पर्यावरण विषयों का संतुलन है, हम उस संतुलन को नहीं रख पाते हैं। मुझे लगता है कि कृषि विकास की नीति को आगे बढ़ाते समय जो जैव विविधता के क्षेत्र हैं, उनके संतुलन को स्थानीय बीज के द्वारा उत्पादन की वृद्धि किस प्रकार करें, के विषय के साथ-साथ खेती और पशुपालन की भी वृद्धि करनी चाहिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से एक और विषय उठाना चाहूंगा। मैं राजस्थान के संदर्भ में कहना चाहूंगा — हालांकि कृषि मंत्रालय द्वारा इस विषय की अनुशंसा की गई है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में जो क्लेम का पैसा है, वह गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है ...**(समय की घंटी)**... लेकिन कृषि मंत्रालय की अनुशंसा भी रहती है। ...**(समय की घंटी)**... मैं केवल दो मिनट में अपने विषय को समाप्त करना चाहूंगा। पश्चिमी राजस्थान का जो मौसम है, जो बारिश होती है, वह हमेशा लेट होती है। जो देश का औसत है, वहां उस औसत से कम बारिश होती है, इसलिए हम सूखे की समस्या और चारे के संकट को झेलते हैं। हम चारे के स्थायी संकट को झेलते हैं। कई बार 90 दिनों की जो तकनीकी व्याख्या है, उस व्याख्या के अंतर्गत यह नहीं आता है। पिछली बार भी माननीय कृषि मंत्री जी ने इस बात को लेकर आश्वासन दिया था। मैं यह कहना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में लगातार देश की औसत से कम बारिश होने के कारण हमें लगातार जिस सूखे का सामना करना पड़ता है, उसका समाधान होना चाहिए। वहां पर मूल रूप से हमारा जो पशुधन है, वही आय का एकमात्र स्रोत है। इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों की अपनी भौगोलिक सीमाओं के कारण अपनी-अपनी परिस्थितियां हैं, उनके संदर्भ में मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस दृष्टि से समग्र विकास की नीति का विस्तार करें। इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो नॉर्म्स हैं, उन पर्टिकुलर क्षेत्रों के लिए जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या है, उन नॉर्म्स को इसमें और थोड़ी ढील देने का प्रयास करें, ताकि हम उस क्षेत्र की समस्या का समाधान कर सकें । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Thank you. Before I call the name of the next speaker, I would like to inform you my that instruction is that each speaker should stick to the allotted time; otherwise, if the allotted time is over, nothing will be recorded. That is my instruction. So, I would appeal to the hon. Members to stick to their allotted time. Now, Dr. Chandrapal Singh Yadav.

डा. चंद्रपाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज आपने हमें एक बहुत ही अहम मुद्दे पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। महोदय, यह कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थ व्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर निर्भर करती है। हिंदुस्तान की 60 फीसदी आबादी सीधे-सीधे खेती से जुड़ी हुई है। अगर खेती करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि इस देश की आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं हो सकती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस बात पर निर्णय लेना चाहिए कि इस देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यहां के किसानों का खुशहाल होना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, जहां इस देश की आबादी बढ़ रही है, वहीं खेती योग्य जमीन दिन-प्रतिदिन घटती चली जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के किसानों ने अथक् मेहनत करके, प्रयास करके इस देश को पूरी तरह से खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकारों ने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या इस देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले लोग आज आत्मनिर्भर हैं और उनकी स्थिति क्या है, इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। अगर सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी, तभी इस देश में खुशहाली हो सकती है।

मान्यवर, किसान पिछले तीन वर्षों से लगातार गर्दिश में है। दैवी आपदाओं का प्रकोप दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। पिछले तीन वर्षों से कभी सूखा पड़ता है, कभी बेमौसम बरसात होती है, कभी ओला पड़ता है, जिसके कारण आज किसान बुरी तरह से कर्ज में फँसता चला जा रहा है। मुझे याद है कि पिछली बार 2007 और 2008 में जब मंदी का दौर आया था, उस दौर में यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार ने उद्योगों को मंदी के दौर से निपटने के लिए एक पैकेज दिया था। इसके निवारण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था। पिछले तीन वर्षों से लगातार किसान दैवी आपदाओं को झेल रहा है। बहुत अच्छा होता अगर भारत सरकार अपने बजट में किसानों के लिए तीन साल की समस्याओं से निपटने के लिए कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान करती। उससे किसान, जो तमाम कर्ज में फँसते चले जा रहे हैं, जिनके पास आज खाने के लिए अन्न नहीं है, उनकी मदद की जा सकती थी, लेकिन सरकार ने अपने बजट में कुछ नहीं किया।

मान्यवर, आज किसान को लाभकारी मूल्य का न मिलना सबसे बड़ी समस्या है। आज हमने कहा कि किसान ने हमें आत्मनिर्भर बना दिया, किसान ने अच्छी पैदावार की, अच्छा गेहूँ पैदा किया, अच्छा धान पैदा किया, लेकिन आज किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मैं सदन के माध्यम से, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा और मैं उन्हें केवल दो सुझाव देना चाहूँगा। हमारे तिवारी जी अभी चले गए। तिवारी जी ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया था कि अभी गेहूँ की कीमत 1,450 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि इसे 7,600 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। तिवारी जी यहां होते, तो हम उनसे कहते कि देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक लगातार किसानों के साथ यही हश्र हुआ है। जब यूपीए की सरकार थी, तब यह 1,250 रुपए प्रति क्विंटल थी। दो साल के बाद तिवारी जी 7,600 रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी यह बात सही है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। आज जो तमाम नौकरी करने वाले लोग हैं, उन्होंने उनसे उनकी तुलना की। आज Fourth Class के कर्मचारी को 16 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही है, जबकि अगर बहुत अच्छा किसान भी हो, तो वह मात्र 3 हजार रुपए प्रति माह से ज्यादा पैदा नहीं कर पाता। इसीलिए

हम कहना चाहते हैं कि अगर Fourth Class के कर्मचारी को 16 हजार रुपए प्रति माह मिल रहे हैं और हर 10 साल में एक वेतन आयोग आता है, अभी सातवां वेतन आयोग आएगा, तो उनकी तन्ख्वाह 30 हजार रुपए प्रति माह हो जाएगी, जबकि किसानों की आय 3 हजार रुपए प्रति माह से 4 हजार रुपए प्रति माह नहीं होगी। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसान के लिए एक आयोग बनना चाहिए और जो किसान की लागत है, जो मेहनत है, उस लागत और मेहनत के अनुसार किसान को लाभकारी मूल्य दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, कर्मचारियों को हर साल महँगाई की किश्त मिलती है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ कर्मचारी ही महँगाई को झेलते हैं, किसान महँगाई को नहीं झेलते? किसान जो एक-एक चीज खरीदता है, वह दिन-प्रतिदिन महँगी होती चली जा रही है। हम चाहते हैं कि प्रति वर्ष उनको भी महँगाई भत्ता मिले, हर 5 साल में उसको रिव्यू भी किया जाए और 5 साल के बाद किसान के लिए लाभकारी मूल्य तय करने के लिए एक आयोग गठित होना चाहिए।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। अभी आदरणीय प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, लेकिन केवल कहने से उनकी आमदनी दोगुनी नहीं हो जाएगी। हम कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी, आप इतिहास पुरुष बन जाएँगे, अगर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, जिस तरह से यूपीए सरकार ने 'महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना' बनाई थी, उसी तरह से आप इस सदन में किसानों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी का कानून लाएँगे। अगर यह कानून होगा कि किसान की आमदनी कम से कम इतनी होनी चाहिए और अगर किसान की आमदनी उतनी नहीं होती है, तो सरकार उसकी भरपाई करेगी, तभी इस देश में किसानों का भला हो सकता है, वरना उसका भला नहीं हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी सीधे-सादे किसान के बेटे हैं और इनके मन में किसान की पीड़ा है। इनको कानून लाना चाहिए और कानून बनाकर इनको यहां के किसानों की मदद करनी चाहिए।

मान्यवर, आज बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि कोई भी किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है, कोई भी किसान अपने बेटे को खेती से नहीं जोड़ना चाहता है और इसके पीछे केवल एक ही कारण है। आपकी जो 'रोज़गार गारंटी योजना' बनी थी, वह मजदूरों के लिए बनी थी, इसलिए आज मजदूरों का पलायन रुक गया है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि मजदूरों का पलायन हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मजदूरों का पलायन मनरेगा से रुक गया है, किन्तु मेरे किसान अपनी इज्जत को ढकने के लिए नहीं बैठे हैं। जो खेती वाले लोग हैं, वे भले ही पलायन करके दिल्ली में रिक्शा चलाना पसन्द करेंगे, दिल्ली में पान की खोली खोलना पसन्द करेंगे अथवा यहां मजदूरी करना पसन्द करेंगे, लेकिन गांव में जिनकी जमीनें हैं, वे वहां नहीं रह कर अपनी इज्जत को बचा रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर न्यूनतम आय की गारंटी वाला कानून आएगा, तो निश्चित रूप से किसानों का पलायन भी रुक जाएगा।

मान्यवर, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं और मैं आपसे बुंदेलखंड के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज बुंदेलखंड की स्थिति बहुत खराब है, वहां के लोग सूखे से जूझ रहे हैं। वहां नदियों में पानी नहीं है, तालाबों में पानी नहीं है, वहां का हैंडपम्प सूखा पड़ा हुआ है और लोगों को पीने तक के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहां लोग बुरे तरीके से परेशान हैं। पिछली

[डा. चंद्रपाल सिंह यादव]

बार वहां पर बेमौसम की बरसात हो गई थी, ओले पड़ गए थे, तब आप लोगों ने मुआवज़े का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक भी वहां के लोगों को मुआवज़ा नहीं मिल पाया है, बीमे का पैसा नहीं मिल पाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने संसाधनों से उनकी कुछ मदद तो की थी, लेकिन सभी लोगों की मदद नहीं हो पाई है।

मान्यवर, हम लोगों ने निवेदन किया था कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार को मदद दीजिए, लेकिन आश्वासन देने के बावजूद भी आप लोगों की तरफ से मदद नहीं मिल पाई। पिछली बार यूपीए सरकार की तरफ से बुंदेलखंड को पैकेज दिया गया था, उस पैकेज में थोड़ा-बहुत काम ही हो पाया था, लेकिन उसके बाद आपकी सरकार ने उस पैकेज को भी बन्द कर दिया। आज बुंदेलखंड का किसान बुरे तरीके से परेशान है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां के लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पैकेट बना करके, जिसमें गेहूं, आटा, चावल और दाल था, वहां के किसानों को देने का काम जरूर किया है, लेकिन उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं, जिससे वहां के लोगों की मदद की जा सके। ...**(समय की घंटी)**... मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार की पूरी तरह से मदद करके बुंदेलखंड के लोगों की मदद करनी चाहिए और उनको सहयोग देना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Thank you. ...(*Interruptions*)..

डा. चंद्रपाल सिंह यादवः वहां पर स्थायी रूप से सिंचाई के संसाधन नहीं हैं। वहां तालाब हैं, नदियां हैं, बांध हैं, लेकिन उनमें पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए आपको बजट देना चाहिए, पैकेज देना चाहिए, जिससे बुदेलखंड के लोगों का भला हो सके और वहां के लोगों की मदद की जा सके।

महोदय, आज के मौके पर, इस सदन के माध्यम से मैं देश की सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं। आपका नारा है कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगुना कर देंगे, लेकिन दुगुना करने के लिए लोगों के पास सिंचाई के साधन नहीं हैं, उन्हें अच्छा बीज नहीं मिल पा रहा है, उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है और बैंकों से उन्हें सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार से हमारा यह निवेदन है कि किसानों को बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Shri K. C. Tyagi.

डा. चंद्रपाल सिंह यादवः जब आप उद्योगों के लिए बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराते हैं, तो किसानों को क्यों नहीं करवा सकते? हम चाहते हैं कि किसानों के भले के लिए उन्हें बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Now Shri K. C. Tyagi. ...(*Interruptions*)...

श्री के. सी. त्यागी (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, ग्रामीण भारत की बदहाली पर चर्चा करते समय अगर कृषि मंत्री जी के साथ-साथ वित्त मंत्री, आपदा मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य मंत्री, फर्टिलाइज़र्स मंत्री और फूड एंड सप्लाइज़ मंत्री भी होते, तो शायद ब्यौरेवार तरीके से अधिक सार्थक बहस हो सकती थी।

राधा मोहन जी, मैं आपके लिए बहुत क्रिटिकल नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। पिछली बार भी मैंने कुछ सुझाव दिए थे। एक सवाल के जवाब में चार दिन पहले आप कह रहे थे कि कुछ लोगों को भूत है। मंत्री जी, हमें भूत नहीं चढ़ा है, हमें जुनून है। धरती मां का सीना चीर कर जब पूरा देश PL-480 खा रहा था, जो अमरीका के पशुओं को खिलाया जाता है, तब हमारे किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसा काम किया कि आज हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं विदेश भेजता है और दुनिया का सबसे ज्यादा चावल विदेश भेजता है। दुनिया में सबसे ज्यादा फल और सब्जी विदेश भेजता है। यह सरकारों की मेहरबानियों से नहीं, यह किसानों का जो पसीना है, उसकी वजह से और कृषि वैज्ञानिकों की वजह से सम्भव हो पाया है।

सर, अब से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। भारत की जो जीडीपी है, उसमें 50 परसेंट की हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्र की थी। आज 14 से 15 परसेंट की रह गयी है। हमारे चंद्रपाल यादव जी जहां के रहने वाले हैं, यह कोई गुस्से की नहीं, यह रोने की बात है कि घास की रोटी वहां के लोग इसीलिए खा रहे हैं, क्योंकि उसे खाने के बाद दिन भर फिर भूख नहीं लगती है। आप पता लगा लीजिए, हम आपके साथ चलते हैं, अगर यह बात गलत साबित हो जाए। 70 लाख आदमी, बुंदेलखंड के दोनों तरफ के, सिर्फ इनके यहां के नहीं, मध्य प्रदेश वाले भी वहां से पलायन कर चुके हैं। कोई आदमी घर कब छोड़ता है, जब दुनिया छोड़ने को मन करता है। राधा मोहन जी, आप तो वहां से आते हैं, जहां महात्मा गांधी गये थे, सूट-बूट पहन कर, लेकिन लंगोट में आये थे। हमारे दूसरे नौजवान मंत्री बालियान जी बैठे हुए हैं, जहां के चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत करके समूचे देश में गांव के और खेत के किसानों को उठाया था। इसलिए मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि शायद आपकी पीड़ा और लोगों के मुकाबले में शायद थोड़ी ज्यादा होगी, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ।

अभी कल-परसों की बात है। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। मैं आपसे ज्यादा अखबार पढ़ता हूँ, यह मैं क्लेम कर सकता हूँ। एक किसान अपनी पत्नी को बेचने का इश्तिहार अखबार के अन्दर देता है। सारे देश के लिए, संसद के लिए, सारे उन सिविल सोसायटी के लोगों के लिए यह डूब कर मरने की बात है, जो यह कह रहे हैं कि भारत तरक्की कर रहा है। मैं उनकी तरफ भी कहना चाहता हूँ। इस देश की जीडीपी जब 9 परसेंट के आसपास थी, जो तथाकथित आर्थिक सुधारक इधर के हों या उधर के हों, देश में उस समय सबसे ज्यादा असमानता थी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे और उन्होंने कहा था कि

(उपसभापति महोदय *पीठासीन हुए)*

जीडीपी बहुत ज्यादा है। राधा मोहन जी, एक बार हमारे नेता डा. लोहिया जी संसद में भाषण कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के एक आदमी की आमदनी 3 आना रोज की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने चेम्बर में थे। लोहिया जी के साथी अशोक मेहता जी प्लांनिग कमिशन के वाइस चेयरमैन थे। जवाहरलाल जी ने उसी वक्त अशोक मेहता जी को बुलाया।

[श्री के. सी. त्यागी]
आज़ादी के आन्दोलन में सब साथ ही थे। उन्होंने पूछा कि क्या डा. लोहिया सच कह रहे हैं? तो ये संवेदनाएँ जब होती हैं, ये कंसर्न जब होते हैं, ये पीड़ाएँ जब होती हैं, तब कुछ अच्छे फैसले लेने में आसानी भी होती है।

क्या आपको पता है कि पिछले साल के मुकाबले में लगभग 47 परसेंट कम बारिश हुई है? 320 जिलों में सूखा है। अच्छा होता यदि गृह मंत्री जी यहां होते। आपदा प्रबंधन का, जिसका जिक्र मेरे साथी कर रहे थे, जिस तरह का मुकम्मल बंदोबस्त होना चाहिए, हमें लगता है कि वह नहीं हुआ है। यह कोई खाद या किसान का ही मामला नहीं है, बल्कि उसके साथ डिपेंडेंट मजदूर हैं, भूमिहीन किसान हैं, उनका भी है। चंद्रपाल जी अभी जिक्र कर रहे थे। एक अच्छा काम जरूर उनकी सरकार के जरिए हो गया, हालांकि जब आर्थिक सुधार इस तर्ज पर हो रहे हों, जिसमें मानवीय संवेदनाएँ न हों, तब कम से कम एनएसी की चेयरमैन ने मनरेगा लगा कर गांव से पलायन रोकने का काम जरूर किया। मैं इस काम भर के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैंने पढ़ा कि समृद्ध किसानों पर टैक्स लगेगा। समृद्ध किसान कहां हैं? मैं आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूँ। भुपिंदर जी आप मेरी इस बात के लिए गवाही दे दीजिए कि 85 परसेंट किसान 2 एकड़ से कम वाले हैं। कहां हैं समृद्ध किसान? किसी जमाने में कहा जाता था कि कुलक हैं। यह भाषा लोगों ने रट ली है और किसानों को प्रताड़ित करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। वे कॉरपोरेट सेक्टर के किसान हैं, जिन्होंने एसईज़ेड बना लिया है। आजकल वे भी खेती कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... ऐसे कामों के लिए उन्हें भुपेंद्र यादव ही याद आते हैं, भूपिंदर सिंह याद नहीं आते। ...**(व्यवधान)**...

सर, मेरा एक भी आंकड़ा गैर-सरकारी नहीं मिलेगा। यह मैं चुनौती से फ्लोर पर कह रहा हूँ। लगभग 42 परसेंट किसान गाँव में ऐसे हैं, जिन पर किसी न किसी तरह का कर्जा है। इन्होंने 3 लाख करोड़ रुपये ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Only two more minutes.

श्री के. सी. त्यागी: 3 लाख करोड़ रुपये का पैकेज इन्होंने देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों को दे दिया। इन्होंने भी पिछले दिनों एक लाख करोड़ की राहत दे दी। हमारी मांग है, हमारे मित्रों ने भी उठाई है। लगभग एक लाख कुछ हजार करोड़ का कर्जा देश भर के किसानों पर है। किसानों की मदद करना चाहते हो तो कार्पोरेट की तर्ज पर इनका भी कर्जा माफ करने का काम करो, वरना आपके सब दावे और वायदे झूठे हैं। "फसल बीमा योजना" की हम तारीफ करते हैं। हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं लेकिन यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मैं राजस्थान का जिक्र आपसे करूं, मगर भुपेंद्र जी, जहां से आप आते हैं, तो वहां पर किस तरह से बीमा में बीमा कम्पनियों को ज्यादा फायदा हुआ, बजाए किसानों के। 20 फीसदी से भी कम किसान अपनी फसलों का बीमा कराते हैं। 46 परसेंट किसानों का बीमा संबंधी काम होता है। वे उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। आपके राजस्थान का केस है कि छः वर्षों में बीमा कम्पनियों ने सिर्फ किसानों से लगभग 1800 करोड़ रुपए की कमाई की, यानी तीन सौ करोड़ रुपए प्रति वर्ष का मुनाफा कम्पनियों को सिर्फ किसानों से हुआ, जबकि बीमा क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को मात्र 50 करोड़ रुपए मिले This is the reality of your so-called *Fasal Bima Yojana*. लेकिन सरकार कहती है, वायदा करती है, हम विश्वास करते हैं लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है।

इरिगेशन के मामले में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, उसमें आपने पहले सालों के मुकाबलों में अच्छा काम किया है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा है। 60 परसेंट जमीन, अब आप उनको तो गाली दे सकते हो कि उनके राज्य में यह नहीं हुआ। हम 40 साल उनके खिलाफ रहे और दो साल से आपसे भी अलग हैं। तलाक हो चुका है हालांकि जो मियाद है इब्बत की, वह अभी खत्म नहीं हुई है, या हो गई है यह मान लीजिए। अब वहां पर हमने अपनी सरकार बना ली, आपसे अलग होकर के। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 60 परसेंट non-irrigated जमीन है उसके मुकाबले में गडकरी जी का जल का जो मामला उन्होंने उठाया है, जिसके बारे में चर्चा थोड़ी देर में आएगी। ...**(समय की घंटी)**... अगर नेशनल इरिगेशन के लिए भी कोई ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः त्यागी जी, प्लीज। ...**(समय की घंटी)**...

श्री के. सी. त्यागीः और यह किसान के लिए, देश की आर्थिक निर्भरता के लिए, कृषि के लिए, सब के लिए इतना काम कोई नहीं हो सकता ...**(व्यवधान)**... ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, Tyagiji. ...(*Interruptions*)... Time is over. ...(*Interruptions*)... Time is over. ...(*Interruptions*)... Mr. Sukhendu Sekhar Roy ...(*Interruptions*)...

श्री के. सी. त्यागीः सर, मैं concluding remarks ही दे रहा हूं। 60 परसेंट की जगह सौ का सौ परसेंट किसान जो है और आज भी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः टाइम ओवर।

श्री के. सी. त्यागीः सर, मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, सुखेन्दु जी, एक मिनट। अभी प्रधान मंत्री जी कह कर गए हैं, उनकी बात का मैं यकीन करता हूं, चूंकि वे देश के प्रधान मंत्री हैं, असहमति रखते हुए भी, कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 में। पहली बात तो यह बात गलत है। अगर हो भी गई तो उस समय प्राइस इंडेक्स क्या होगा? क्या बिजली का दाम यही होगा, क्या कपड़े की सिलाई यही होगी, क्या कार का दाम यही होगा? पहली बात तो यह है कि यह डबल इसलिए भी नहीं हो पाएगी कि आपके पास कोई ऐसी integrated plan नहीं है, जहां 42 परसेंट किसान खेती छोड़ने वाले हों, वहां दोगुनी आमदनी होगी, यह वोट लेने के लिए तो अच्छा हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, with your kind permission, I would like to speak in Bengali. Before that, I will speak a few lines in English. Some figures have been given by the Minister of State in the Ministry of Agriculture in the other House on 1st March, 2016 in reply to Unstarred Question No.913 and it appears from the reply that the total farmers suicide cases reported during 2015 all over the country are only 1,690, and out of which 725 farmers committed suicide in Maharashtra alone. But one report published in The Hindu on 14th January, 2016, *inter-alia*, states that, and I quote one line with your permission, "The data obtained from the Government shows Vidarbha was the worst hit last year, with around 1,541 farmers from Amravati and Nagpur division committing suicides."

[Shri Sukhendu Sekhar Roy]

यह गवनर्मेंट डेटा का उल्लेख करके बोल रहे हैं, यह सरकार की तरफ से कुछ अलग है, जिसमें आसमान-जमीन का फर्क है।

Now, Sir, I would like to switch over to Bengali in view of the fact that * Sir, the condition of the farmers engaged in jute cultivation in our State has become precarious owing to the wrong policies adopted by the Central Government. Sir, I want to tell that just before the new Government was formed, BJP declared on page 28 of its election manifesto, "BJP will take steps to enhance the profitability in agriculture by ensuring a minimum 50 per cent profit over the cost of production." Many Hon'ble Members said that the Minimum Support Price (MSP) for jute has no scientific basis for evaluation. No scientific system is being followed to fix Minimum Support Price, Sir; it is rather being done in a haphazard way. MSP is being fixed on the data provided by different organizations and agencies. Even there is no scientific assessment on the quantum of jute farming and production in West Bengal – Jute Corporation of India provides some data, Jute Baler's Association gives another data and IJMA provides yet another differing account. So I appeal to the Government through you, Sir, to assess the reasons why jute production is alarmingly decreasing in our State. It is not a matter that concerns West Bengal only; there are 7 States in India where cultivation of jute has been going on for centuries together. Jute is being cultivated across 8 lakh hectares of land in our State and as you know well, Sir, jute is an essential commodity. There are 77 jute mills spread across the country. I am happy to State that the oldest jute mill of the country and also the largest number of jute mills can be found in West Bengal. Unfortunately, Sir, the Government has not been providing adequate Minimum Support Price for jute and so, thousands of jute industry workers and jute farmers along with their families are languishing in a terrible pool of distress. But the Government did not pay heed to their distress. I would request the Government through you, Sir, to fix the Minimum Support Price for jute at a level higher than the '*mandi*' or market price so that the farmers feel encouraged to cultivate and produce more jute. During the last 2 years, the Minimum Support Price for jute was at such a low level and added to that the price of jute dipped in such a way that the jute growers had no other option than to agree to distress sells. So our Hon'ble Chief Minister Ms. Mamata Banerjee provided an additional compensation of ₹ 500 per quintal to the jute cultivators. We had repeatedly appealed to the Central Government at that time but it fell on deaf ears. So once again I take this opportunity to request the Government through you Sir, to fix the Minimum Support Price of jute above the '*mandi*' price or market price. It should not be applicable to our State only; it should rather be applicable to all 7 jute-producing States of the country. I want to stress

* English translation of the original speech made in Bengali.

the fact that the Minimum Support Price announced for this season too is not all adequate. The condition has turned more unbearable because a group of jute mill owners have hiked the price of raw jute in an artificial way; they have artificially created a crisis of jute availability and have been deceiving the jute farmers. We cannot tolerate the unfair means by which these jute mill owners are making profit. We appeal to the Government through you, Sir that the Minimum Support Price of jute must be increased to a level above the market price; otherwise the growers will not take interest in cultivation of raw jute.

Sir, in conclusion let me say that BJP had declared in its manifesto – I am quoting from the manifesto of the BJP – "Genetically modified food will not be allowed without full scientific evaluation." Yet we do not know what kind of evaluation is being done on GM crop. Public in general has been kept in the dark on this aspect. All the information regarding evaluation should be published in the website of the Ministry of Agriculture so that public can become aware of the evaluation and they can voice their opinion about GM crop and take decisive steps in choosing the right one. The farmer community of the country should be consulted before taking any decision on GM crop; otherwise we will face similar kind of crisis that saw widespread destruction due to cultivation of Bt cotton in Vidarbha region in Maharashtra. The farmers of the country will have no choice other than committing suicide like the farmers in Vidarbha – we can never tolerate this kind of wretched condition. So I appeal through you to the Government to make public all the information regarding scientific evaluation of GM crop.

Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. It is very kind of you. Now, Shri Navaneethakrishnan. Please adhere to the time.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Definitely, Sir. I thank hon. Deputy Chairman and I also thank hon. Amma for the opportunity given to me to speak on this issue. I am going to give a positive side of agriculture in the State of Tamil Nadu. The State has adopted many techniques; it has improved the foodgrains production; and, it has reached at the maximum level in ten years. Sir, I may be permitted to quote statistics. During 2011-12, the State of Tamil Nadu created history in the field of agriculture in the State with highest foodgrains production of 10,152 lakh, which is, 10.152 metric tonnes, which is an all-time high in the last ten years. The State has also achieved the highest production in rice, millets and pulses. How has it been possible, Sir? Hon. Amma has introduced a novel scheme, a technology called System of Rice Intensification (SRI). This technology is giving the highest yield to all the farmers. Sir, I am very glad to inform this august House that consecutively

[Shri A. Navaneethakrishnan]

the Tamil Nadu farmers are getting the Union Government's award, namely, Krishi Karman Award carrying a cash prize of rupees one lakh. For the current year, our lady farmer, T. Amalarani from Tirunelveli has received a sum of rupees one lakh from the hon. President, Shri Pranab Mukherjee, in New Delhi on 15th January. As per the scheme in place, which is implemented by hon. Chief Minister, Amma, she has also received a sum of ₹ 5 lakhs because she has produced 18,143 kilos of paddy per hectare using the SRI technique. I humbly submit that the State of Tamil Nadu has achieved the maximum foodgrains production including pulses, millets and everything. How could it be achieved? Hon. Amma has introduced many novel schemes. I do not want to take much time of the august House.

Sir, regarding water management, everybody must learn from Amma. To get the water from Cauvery, she has waged an all-out war to see to it that the award passed by Cauvery Water Tribunal is given effect to. Because of the efforts taken by her, the award passed by the Cauvery Water Tribunal was given effect to, and, further as a fallout, the Central Government had to constitute the Cauvery Water Management Board, and, also the Irrigation Management Committee, which is yet to be done. Further with regard to the Mullaperiyar dam, she has won the case before the Supreme Court and the southern parts of Tamil Nadu are getting water for agriculture.

Now, with regard to the crop insurance also, hon. Chief Minister, Amma, has provided a sum of ₹ 30 crore for the purpose of paying crop insurance premium. In all aspects, she is implementing the Soil Health Management, crop-based interventions, Input Supply Management and Integrated Farming System, and, the SRI techniques are being adopted in 1,880 villages throughout the State. That is why, consecutively, our Tamil Nadu farmers are able to get the Central Government award as well as cash award of ₹ 5 lakhs each year, which are given by hon. Amma to the highest producer of paddy or foodgrains. I would also like to point out the financial position of the farmers. Now, hon. Amma has established Direct Purchase Centres throughout the State. Wherever farmer wants to sell his produce, he can sell it easily without any difficulty. They also get a very good price. So, in Tamil Nadu, there is absolutely no problem for any kind of farmers. But, at the same time, regarding the credit facilities, I had earlier urged the Central Government that the Non-Performing Assets concept must be done away with. So, while sanctioning the loans for these agriculturists, do not adopt this principle of Non-Performing Assets. They are not able to repay it. Agriculture is dependent upon the natural factors. I have already submitted it.

Also, regarding the interest subvention, at the risk of repetition, I would like to

urge all the hon. Members and experts in economics and I urge the hon. Minister for Agriculture also, that this interest subvention scheme is benefitting only the businessmen as per reports available in the newspapers. So, the appropriate steps must be taken by the Central Government to see that the benefit of the interest subvention scheme goes to the farmers. Otherwise, the farmers are in the darkness. No farmer knows the fact that if the loan amount is repaid on time, definitely, they are entitled for refund of the part of the interest. That is not known to the farmers. Hence, awareness must be created among the farmers. The Central Government must do it.

Also, the farmers must get the loan, and for all other needs, all the twelve months in a year. Seasonal loan now disbursed, may be, only for the summer season, only for the *kuruvai* season, is not good. That is why farmers are living in indebtedness. So, to save the farmers, kindly frame good regulations. Also, implement them properly. The other day also, I submitted that the concept of inclusive growth is being implemented properly by hon. Amma. Hence, I thank once again the hon. Amma because all the farmers in Tamil Nadu are very happy. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much, Mr. Navaneethakrishnan. Now, Shri Rajpal Singh Saini. आपकी पार्टी का समय छह मिनट है। आपको छह मिनट में समाप्त करना है। सबके लिए एक ही नियम है।

श्री राजपाल सिंह सैनी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है और यह सच भी है, लेकिन एक दूसरी भावना भी है, जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं। हम केवल उत्पादन की चिंता करते हैं, लेकिन उत्पादन करने वालों की नहीं, उनके बारे में हम नहीं सोचते। जब देश आज़ाद हुआ था तब किसान गर्व से कहता था कि मैं किसान हूं। इस बात को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन आज किसान को यह कहने में शर्म आती है कि मैं किसान हूं, क्योंकि उसकी इज्जत समाज में नहीं रह गई है।

मान्यवर, उस टाइम किसान अपने बच्चों को पढ़ाकर खेती में लगाता था और यह कहावत भी थी, "उत्तम खेती, मध्यम बान"। आज किसान अपने बच्चों को पढ़ाकर, चाहे जैसे भी हो, उनको नौकरी दिलाने की कोशिश करता है और बाहर काम करवाने की सोचता है।

मान्यवर, 1951 में भारत में 71 प्रतिशत किसान थे, लेकिन 2011 की कृषि गणना के मुताबिक किसानों की संख्या घटकर 45.01 प्रतिशत बची है। हमारे 26.09 प्रतिशत किसान गायब हो चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि किसानों का मोह खेती से भंग हो रहा है और वे कृषि में पिछड़ रहे हैं। जिसका दादा कभी 100 एकड़ जमीन बोता था, 50 एकड़ जमीन बोता था, आज उसका पोता एक सीमांत किसान बन गया है या मजदूरी करने को मजबूर है। जिसके पास छोटे से छोटा उद्योग था, वह आज बड़ा उद्योगपति, अरबपति, खरबपति बन चुका है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री टी.के. रंगराजन)** *पीठासीन हुए*]

[श्री राजपाल सिंह सैनी]

5.00 P.M.

महोदय, व्यापार घोड़े की चाल चल रहा है और कृषि कछुए की चाल से चल रही है। आज किसान की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उसकी स्थिति को वे लोग नहीं जानते, जो उसके द्वारा तैयार की गई उपज का भाव तय करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि किसान कितनी परेशानी उठाकर, अपने पूरे परिवार को लगाकर, अपनी फसल तैयार करता है। कितनी कड़ी मेहनत उसको अपने परिवार के साथ करनी पड़ती है। कड़ाके की सर्दी में जब रात को दो बजे बिजली आती है, तब अंधेरी रात में, अपने बच्चों के साथ उठकर जंगल में जाकर, वह अपना ट्यूबवैल चलाता है, तब कहीं जाकर सिंचाई करने का काम करता है। जो लोग उसकी फसल का भाव तय करते हैं, उनको यह भी नहीं पता कि एक एकड़ में कितना बीज, कितनी खाद, कितनी बार जुताई और कितनी बार निराई करनी पड़ती है। जब तक किसान की फसल का भाव टाई लगाकर, AC room में बैठकर तय होता रहेगा, तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। किसान का भला तब होगा जब उसकी फसल का लाभकारी मूल्य तय करते समय धोती वाला किसान उनके बीच में बैठेगा, जिसको यह पता है कि कितनी लागत और कितनी मेहनत किसान को करनी पड़ती है।

महोदय, अभी माननीय प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे कि किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने तो चुनाव से पहले भी वायदा किया था कि मुझे प्रधान मंत्री बनाओ, मेरी सरकार को केंद्र में लाओ, तो मैं किसान को उसकी लागत का 50 per cent बढ़ाकर दूंगा, डेढ़ गुना बढ़ाकर दूंगा। यहां हमारे दोनों कृषि मंत्री बैठे हैं। वे चाहते भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके वश की बात नहीं है कि किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिले। वे लाभकारी मूल्य तो दें, तभी तो किसान की आमदनी दोगुनी होगी, तभी तो किसान को उसका लाभ मिलेगा। जो डेढ़ गुना की बात करते थे कि किसान की लागत का मूल्य दूंगा, उसकी शुरुआत तो करें, तभी तो किसान को लाभ होगा।

मान्यवर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं और मुजफ्फरनगर मेरा जनपद है। मेरे एक मंत्री मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं और वे भी जनपद मुजफ्फरनगर के ही हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने की फसल मुजफ्फरनगर में होती है। आज गन्ना किसान की क्या दुदर्शा हो रही है, उसे गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार से मिल-मालिकों को जितना ऋण चाहिए था, उनको बगैर ब्याज के ऋण दे दिया गया। दूसरी तरफ किसानों को गन्ने की पेमेंट नहीं की जा रही है, किसान को गन्ने का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, किसानों को गन्ने का रेट सही मिला और टाइम से मिला। अगर पेमेंट टाइम पर नहीं हुई, तो हिन्दुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ था कि बहन कुमारी मायावती ने ब्याज के साथ किसान को उसका पेमेंट कराया था। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है, माननीय प्रधान मंत्री यह व्यवस्था क्यों नहीं करा देते?

मान्यवर, किसान के लिए एक विडम्बना और है। किसान के ऊपर अगर एक हजार, दो हजार या पांच हजार रुपए कर्ज़ है, तो तहसीलदार उसको लॉकअप में बंद करवा देता है। दूसरी तरफ देखिए, दस-दस हजार लाख व करोड़ रुपए उद्योगपतियों पर कर्ज़ है, लेकिन उनको कोई टोकता भी नहीं है। इस तरह से किसान का खेती से मोहभंग हो रहा है। महोदय, डा. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर पूर्णतः लागू हो जाती, तो किसान का भला हो सकता था, क्योंकि आयोग

ने कहा था कि किसान को उसकी लागत का 50 प्रतिशत मूल्य अधिक मिलना चाहिए। उसमें खाद, बीज व पानी के साथ-साथ किसान की जमीन, उसका परिश्रम, उसकी मज़दूरी व उसके पूरे परिवार के द्वारा किए गए कार्यों को भी जोड़ना चाहिए। दैविक आपदा भी किसान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। कभी बाढ़, कभी सूखा तो कभी ओलावृष्टि किसान की फसल को नष्ट कर देती है। किसान को उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 15 रुपए का चैक, 20 रुपए का चैक दिया जाता है और कभी-कभी तो उसे सरकार द्वारा 13 रुपए का चैक भी थमा दिया जाता है, जिसको कैश कराने के लिए किसान बैंक में भी नहीं जाता है। यह किसान के साथ मज़ाक नहीं तो और क्या है? जंगली जानवर भी किसान की खड़ी फसल को बरबाद कर देते हैं। इन सभी समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा। किसान की उपजाऊ जमीन को उद्योगपति अपने उद्योग लगाने के लिए सस्ते दामों पर अपने नाम करा लेते हैं, लेकिन वे उस जमीन पर उद्योग नहीं लगाते और उनकी वह जमीन बरसों तक खाली पड़ी रहती है। फिर उसकी श्रेणी चेंज़ करवाकर बाजार में उसे ऊंचे दामों पर बेच देते हैं।

महोदय, मेरा सुझाव है कि उद्योग लगाने के लिए बंजर या पथरीली जमीन उद्योगपतियों को देनी चाहिए। ...**(समय की घंटी)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN): Please conclude.

श्री राजपाल सिंह सैनीः मान्यवर, एक मिनट बोलने दें। मैं नया मैम्बर हूं, इसलिए एक मिनट बोलने दें।

हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश होना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार थी तो यह प्रस्ताव भेजा गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी पैदावार होती है कि अगर अलग उत्तर प्रदेश बन जाए, केंद्र सरकार मेहरबान हो गई, तो हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया में भी इतनी ज्यादा फसल पैदा नहीं होगी जितनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगी। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान मेहनती है और वह मेहनत करके दिखाएगा। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN): Please conclude.

श्री राजपाल सिंह सैनीः मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले ...**(व्यवधान)**...

डा. चंद्रपाल सिंह यादवः ये पहले विधान सभा से पास करके भेजते नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**... यहां से चिट्ठी लिख कर भेज देते हैं।

श्री राजपाल सिंह सैनीः चंद्रपाल जी, विधान सभा ने पास करके भेजा है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN): Please conclude.

श्री राजपाल सिंह सैनीः सर, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसान की दयनीय स्थिति को देखते हुए जो चुनाव में वायदे किए गए थे, उन सभी को पूरा करें और किसानों के साथ न्याय करें, धन्यवाद।

SHRI C. P. NARAYANAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, during the last two or three years in every session we are having a discussion on the plight of farmers in

[Shri C. P. Narayanan]

India. When the NDA Government came to power we find that there is 26 per cent rise in suicide by farmers. Why is it happening? It is happening because of floods sometimes, drought sometimes and other kinds of problems due to which agriculture, including commercial crops has failed. There has been no solution either during the period of the UPA Government or during the period of the NDA Government. I do not want to go into much details about it. But today our respected Prime Minister was telling us that to save kisans in India, the Government is trying to have a tie up with Coca-Cola. We have had experience in various parts of India of tying up farmers with Indian or foreign corporates, it is the farmers who will be finally in trouble. Finally, they will have to commit suicides. There is no other way. So, that is not the solution. The Government has to come, in a big way, to help farmers by providing much more than ₹ 20,000 crores or ₹ 30,000 crores. The population of farmers in the country is 50 to 60 crores. Unless you invest per year ₹ 1,00,000 crores it is of help. Even if you are spending ₹ 1,00,000 crores, it will work out to ₹ 2,000 per head. Unless that kind of investment is made by the Government it will not be of any help to farmers in India.

I want to particularly state about what is happening in my State, Kerala. The rubber farmers are in great difficulty because of the fall in prices. So, also is the cardamom farmers. Recently the coconut farmers are also suffering due to steep fall in price. These three sections of farmers form a big section of our population. The fall in prices of these commodities is happening because of our country's agreements with the ASEAN and other countries. Various kinds of agriculture products are coming into our country. Our farmers are finding it difficult to get a reasonable price for their products. We have been pressing the NDA Government and the previous Government to ensure a reasonable price for these commodities but with no success. The Government has to come to the help of these farmers not only in Kerala, but also in other States. With regard to foodgrains and other commodities also this problem is there. Two things have to be done. One is, we have to revisit our agreements with various countries. You have to remember that countries which are advanced in the field of agriculture, whether it is the U.S., or the European countries or Far Eastern countries, they are giving help to the farmers in a big way, not in a small way as we are doing. That kind of help should be ensured to our farmers; and that help should not be routed through corporates. The Government has to directly help the farmers either through cooperatives or the Government agencies should themselves purchase commodities from farmers. For this purpose the Government has to set aside a very big amount. The poor and small farmers have to be helped in a big way not only in the purchase of commodities but also in their walks of life. So, PDS needs to be ensured to them; they are almost 50-60 per cent of the total population, if not more. I am talking about the agrarian population.

Then, the educational facilities, medical facilities and others that are being given to the middle class employees and other sections, must also be extended to the children and other family members of farmers. It is only in this way that we can help the farmers. Otherwise, what will happen? We would only be having these discussions repeatedly, every time with no particular purpose. If there is a purpose, I would request the Minister, and through the Minister, the Government, that they have to have a new policy on farmers, which is not what the Prime Minister had explained today. Without that, I don't think we would be able to look after the farmers and prevent the increasing rate of suicides by farmers in various States.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN): Thank you. Shri Bhupinder Singh; four minutes.

SHRI BHUPINDER SINGH (Odisha): Sir, I would take two more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN): No, Sir.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, through you, I would like to draw the attention of the Agriculture Minister to the fact that a letter has been sent by our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, on the 5th of February, 2016, regarding irrigation projects in Odisha. The projects include the Upper Indravati Extension Project, Rukura Irrigation Project, Lower Indra Irrigation Project, Subernarekha Project, Anantpura Barrage, etc. There are 46 projects in our priority list of major and medium irrigation projects of the country that are to be completed in the next three years.

Sir, it was a commitment that these projects would be funded by AIBP in the ratio of 90:10. Similar is the case about the irrigation project in my own constituency in Kalahandi, Ret Medium Irrigation Project, Telengiri Major Irrigation Project, Koraput also. Now, the AIBP has been converged into the *Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana;* you have made it a ratio of 60:40. Sir, it is a burden on many States of the country, including Odisha. So, specifically, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने 5.2.2016 को जो चिट्ठी लिखी है, अगर उसके ऊपर आज आप यहां जवाब नहीं देंगे, तो बाद में इसके बारे में हमें लिखिए, हम आपके कलीग के साथ बात करेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रधान मंत्री जी को एक और चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ओडिशा में किसान को 3 परसेंट इंटरेस्ट पर लोन देते हैं और जो timely payment करता है, उसके लिए वह 2 परसेंट हो जाता है। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि उसको एक परसेंट किया जाए। अभी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। Farmers का welfare तभी साबित होगा, जब आप इन सब बातों के ऊपर गौर करेंगे।

सर, अरुण जेटली जी और प्रधान मंत्री जी को भी इस सम्बन्ध में लिखा गया था। आपने पॉलिसी बनाई है कि जो agriculture loan होगा, वह नाबार्ड 45 प्रतिशत देगा। नवंबर में पिछले सेशन में लोक सभा के सभी 20 सदस्य और हमारे यहां के सभी सदस्य, हम 28 सांसदों ने मिल

[Shri Bhupinder Singh]

कर प्रधान मंत्री जी से 1,300 करोड़ रुपए State Cooperative Bank के लिए गुहार की थी, लेकिन अभी तक हमें इसके ऊपर कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है, तो हम कैसे सोचें कि इस देश का किसान इस सरकार और आपके माध्यम से सुरिक्षत है?

सर, सबसे खेद की बात यह है कि ओडिशा में जो drought हुआ था, उसके ऊपर High Power Committee ने 1,017 करोड़ रुपए independently देने के लिए कहा, लेकिन आपने उसको काट कर 815 करोड़ बनाया। उसके बाद आपने SDRF के 50 परसेंट शेयर की बात करके उसमें 214 करोड़ रुपए फिर काट दिए। 5.2.2016 की वह चिट्ठी आपके पास आई है। हमारे जो रिलीफ कमिश्नर हैं, उन्होंने इसे आपके Joint Secretary, Disaster Management को दिया है। चूँकि समय नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि आज पूरे देश का किसान दुखी है। आप इसको स्वीकार कीजिए। मैं इसके लिए सरकार को दोषी नहीं बनाना चाहता। मैं आपको निन्दित नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस हाउस के माध्यम से आप इस बात को स्वीकार करें। अगर इस देश में आज कोई दुखी है, तो किसान है, कोई भी exploited है, तो वह किसान ही है। आज अगर सबसे बड़ा अधिकार किसी का है और सबसे अधिक पसीने का पैसा किसी का है, तो वह केवल किसान का है। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN): Thank you.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, two more minutes, I have requested you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN): Please conclude.

श्री भूपिंदर सिंहः सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने आपसे कहा था कि drought का जो फंड है, अभी तक आपने उसका एक भी पैसा रिलीज़ नहीं किया है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अभी तक स्टेट को इसका एक भी पैसा रिलीज़ नहीं हुआ है। सर, आज सारे देश में ओला पड़ा है। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN): See, nothing goes on record. Nothing goes on record. Now, Shri D. Raja.

SHRI BHUPINDER SINGH: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN): Please take your seat. Please take your seat.

SHRI BHUPINDER SINGH: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN): Bhupinderji, please co-operate.

SHRI BHUPINDER SINGH: *

---

* Not Recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN): Bhupinderji, nothing goes on record. Nothing goes on record. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUPINDER SINGH : *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN): Thank you. Thank you.

SHRI BHUPINDER SINGH : *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN): The Minister will reply.

SHRI BHUPINDER SINGH : *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN): See, nothing goes on record. ...(*Interruptions*)... Please sit down.

SHRI BHUPINDER SINGH : *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN): Now, Shri D. Raja. Please conclude within five minutes.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): It is a very important discussion. In fact, as part of the Budget, we will be discussing it further. Here, I limit to certain points. Sir, everyone knows, agriculture is in deep crisis. ...(*Interruptions*)... Our farmers are passing through unprecedented distress. There are fundamental causes for this situation. Farmers do not get remunerative price for their produce. They are facing indebtedness. In fact, debt is a big problem for farmers. That is one of the reasons for increase in suicides. The condition of agricultural workers is very pathetic and worse. In such a situation, what should the Government do? That is what I want to concentrate on at this point of time. Sir, 40 per cent of rural households do not have land. Those who have land, out of them, almost 80 per cent are poor and marginal farmers. How do we protect these small and marginal farmers and agricultural workers? The minimum living income should be guaranteed. Agriculture is not just about production and yields. Here, I suggest that a Farm Income Commission should be set up. Government can consider the suggestion to set up a Farm Income Commission because there is no announcement in this regard. I would like to know from the Agriculture Minister whether he can decide with an open mind to set up a Farm Income Commission because the unprecedented inequalities, which are emerging due to wrong economic policies, are affecting the farming sector also. Societal disparities will increase hugely if we do not address this issue. Sir, natural disasters will not be freak incidents hereafter due to climate change. And, even in this Budget, the outlays for disaster relief is less and the Government will have to rethink on this,

* Not Recorded.

[Shri D. Raja]

how to increase the disaster relief. In terms of agricultural technologies, we need low-cost, low-risk technologies. We should not leave the farmers to the mercy of agricultural business corporations. We have got proper extension systems today. But we should improve the extension systems for right kind of farm advice. Extension systems should be strengthened. The Government will have to think over it. Sir, the woman farmers are unrecognized despite their enormous contribution towards agriculture and agrarian economy. Their rights, especially, to resources like forests and grazing lands should be protected. This is not really one of our focus issues. But now I appeal to the Agriculture Minister to take up this issue seriously. The Government is going in for free trade agreements, including deals in WTO, finally, ending up creating adverse markets for our farmers. We need more and more debate and more assessment before the Government signs any deal.

The other issue is, this Budget talks about decentralization of agricultural produce. What do you mean by decentralization of agricultural produce? Is it to wind up the Food Corporation of India? What is your idea? What is the thinking of the Government? It does not talk about the Food Corporation of India. When you talk of decentralization of agricultural produce, what really do you mean? Sir, there is no Central legislation for agricultural workers. At least, now can you take it up at the Cabinet level and come forward with a Central legislation for agricultural workers? The condition of agricultural workers is very pathetic and miserable; they do not get even minimum wages in many parts of the country. There is no social security coverage for the agricultural workers. There is no universal pension scheme implemented in order to protect the agricultural workers. Unless we have a Central legislation, the agricultural workers cannot be protected. So, I think the Agriculture Minister must address some of these issues and take up these issues with the Cabinet and come forward to Parliament with their suggestions. We will all take up our position on those issues. These are my suggestions at this point of time. Thank you.

श्री पी. एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

सर, आज किसान और किसानी एक संकट के दौर से गुजर रही है और पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, जो हर प्रदेश से संबंधित हैं। महाराष्ट्र उसमें सबसे ऊपर है। मेरे पास ये आंकड़े भी हैं कि आत्महत्या करने वालों में स्मॉल और मार्जनल फार्मर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके ऊपर जो चिन्ता जतानी चाहिए थी, वह पूरी तरह से नहीं जताई गई। केंद्र सरकार का इसमें जो रेस्पोंस है, वह भी बहुत उत्साहजनक नहीं है। अभी बजट पेश हुआ। बजट में सुर्खियों में यह हुआ कि पहले सरकार की छवि सूट-बूट की सरकार की थी, उसको बदलने का प्रयास किया गया, अब किसान और गरीब की तरफ झुकाव हुआ तथा बजट में अनेक तरह के प्रावधान भी किए गए।

सर, मैं बजट के बारे में बताना चाहूँगा। यह कहा गया कि 35,983 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, लेकिन इसी में जो पहले इंटरेस्ट सब्सिडी का अमाउंट 15,000 करोड़ रुपये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज़ के हेड में होता था, उसे एग्रीकल्चर में ले आये। अगर इसको कम कर दिया जाए, तो 20,983 करोड़ रुपये रहते हैं। 2013-14 में एग्रीकल्चर के लिए 21,933 करोड़, 2014-15 में 22,652 करोड़ और 2015-16 में एकदम 5,000 करोड़ रुपये कम करके 17,004 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। तो यह बजट में बढ़ा कर दिया है, इससे कोई खास लाभ मिलेगा, यह मैं नहीं समझता। और दूसरा "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" अच्छी योजना होगी लेकिन उसका पूरा विवरण हमारे सामने नहीं आया। वह अगर आ जाएगा तो उसके बारे में देखा जाएगा। लेकिन अभी जो के.सी.सी. के माध्यम से किसान के लिए बीमा की व्यवस्था है, वह पूरी तरह से असंतोषजनक है। मैं समझता हूं कि उन कमियों को दूर किया जाएगा। सरकार ने कहा कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को डबल कर देंगे। अच्छी बात है। सरकार का कार्यकाल तो 2019 तक है। किस आधार पर कहा कि 2022 तक हम डबल कर देंगे और फिर उसके बारे में आपकी क्या रणनीति है, क्या आप जो उसकी एम.एस.पी. प्राइस है, उसको डबल करने जा रहे हैं? क्या आपने जो निर्णय लिया, हालांकि आपने अपने मेनिफेस्टो में कहा था कि हम डेढ़ गुना कर देंगे लागत का 50 फीसदी बढ़ाकर एम.एस.पी. फिक्स करेंगे और बाद में सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एफेडेविट फाइल होता है जिसमें कहते हैं कि हम इसमें विश्वास नहीं करते। हम एम.एस. स्वामीनाथन की रिकमंडेशन को नहीं मानते। तो यह किस स्ट्रेटेजी के तहत आप डबल इन्कम करेंगे, यह बात भी समझ में नहीं आई। दूसरा, मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि 2022 की बात तो हो रही है, फसल बीमा की बात हो रही है, बहुत सी अलग योजनाओं की बात हो रही है, जो पहले भी योजनाएं थीं उनकी भी बात हो रही है। लेकिन संकट तो आज है। लांग टर्म में भले ही ये सब चीजें ठीक हों, "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" बहुत कारगर हो, जिस पर मेरी शुभकामनाएं हैं और उसमें अविश्वास करने का मुझे कोई कारण नहीं है। यह आगे के लिए हो सकता है, लेकिन तत्काल किसान को क्या राहत दे सकते हैं, यह तो सामने आना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस किसान तक पहुंचनी चाहिए, बेटी की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाई करनी है, उसको खाने के लिए चाहिए, इन सब के लिए उसके पास धन नहीं है। वह सरकार की तरफ से उपलब्ध होना चाहिए। जब ऐसी परिस्थितियां थीं, तो यू.पी.ए. सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया और आज भी वैसी परिस्थितियां हैं। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर यह नहीं भी कर सकते, आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे लेकिन कम से कम जो इंटरेस्ट है किसान का, वह तो आप दो साल का वेव कर सकते थे। लेकिन उस ओर भी आपने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। के.सी.सी. का क्रेडिट, छः महीने में उसका रिन्युअल होता है और छः महीने के बाद फसल तो खराब हो गई, वह वापस अदायगी कर नहीं सकता, रीपेमेंट कर नहीं सकता। तो उसका क्या इलाज है? क्या आपने उसको रोल-ओवर किया कि कोई बात नहीं इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलेगी, भले ही आप पेमेंट नहीं कर पाए हों, तो इसकी व्यवस्था मैं समझता हूं कि पूरी तरह से होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई है। ...**(समय की घंटी)**... मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बस एक मिनट भी नहीं लगेगा।

पूरे देश में टोटल 13 करोड़ खातेदार हैं और के.सी.सी. 8 करोड़ लोगों के पास में है। जो क्रियाशील हैं, ऑपरेटिव के.सी.सी. हैं, वह केवल सवा दो करोड़ हैं। तो इसमें किस तरह से क्रेडिट

[श्री पी. एल. पुनिया]

किसानों को कैसे उपलब्ध कराएंगे? क्या आत्महत्या करते ही रहेंगे और आप देखते ही रहेंगे? तो तत्काल उसको आवश्यकता है। वह आई.सी.यू. में भर्ती है, उसका इलाज ठीक से होगा नहीं, तो मैं समझता हूं कि सरकार को और संवेदनशील होने की आवश्यकता है इसलिए इस पर जरूर जल्दी से जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब): सर, बहुत अच्छा एक डिस्कशन और एक अच्छे इश्यू पर बातचीत हो रही है। आज जब सुबह मेरे पास कुछ अखबार आए तो मन में एक वेदना और चिंता हुई। यह पंजाबी का अखबार है जिसमें लिखा है कि "इस हफ्ते विच हड़पे नौ खेतां दे पुत्तर" इसका मतलब है कि हफ्ते में 9 किसानों ने पंजाब के एक जिले में आत्महत्या की। जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो स्टोरी सभी 9 किसानों की है, लेकिन उनमें से एक किसान की अजीबोगरीब स्टोरी मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उसने अपना परिवार चलाने के लिए खेती के साथ पशु भी रखे हुए थे। लेकिन जब खेती का बोझ बढ़ता गया तो लोन वापस करने के लिए उसने अपने पशुओं को बेच दिया। वह और गरीब हुआ, तो गांव वालों ने इकट्ठे होकर उसको कहा कि ऐसा करते हैं कि आपकी एक भैंस आपको वापस दिलवाते हैं, ताकि आप अपना घर चला सकें। जब फिर भी उसका घर नहीं चला, तो ultimately उसने आत्महत्या कर ली। ये अलग-अलग किसानों की अलग-अलग कहानियां हैं। जब हम किसान के बारे में पढ़ते हैं, तो कभी हम उसको अन्नदाता कहते हैं... जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधान मंत्री थे, तब "जय जवान, जय किसान" का नारा दिया गया। वह इसलिए दिया गया — हम सबको याद है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हम बाहर से जो कनक लेते थे, वह कनक खाने लायक नहीं थी, तो उस समय प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया कि हम सब लोग एक दिन का व्रत रखेंगे। एक दिन व्रत रखने का जो निर्णय था, उसको लोगों ने ऐक्सेप्ट किया, लेकिन उस समय भी किसान को तकलीफ हुई और उसने कहा, नहीं, एक दिन का व्रत रखने की बजाए हम अपने खेत में इतनी पैदावार करेंगे कि लोगों को व्रत रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इतनी मेहनत करने के बाद किसान ने खेती की, तब उसको नाम दिया, "जय जवान, जय किसान" और "अन्नदाता।"

सर, किसान से जुड़ी क्या-क्या चीजें हैं? किसान से जुड़ी हुई चीजों में लेबर है। अगर किसान खेत में काम नहीं करेगा, तो लेबर बेकार हो जाएगी। किसान से जुड़ी हुई agriculture equipments बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा, तो इंडस्ट्रीज़ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। किसान जो खाद यूज करता है, उस खाद को बनाने वाली फैक्ट्री किसान से जुड़ी हुई है, कमिशन एजेंट्स किसान से जुड़े हुए हैं। ऐसे दुकानदार, जो स्प्रे, बीज वगैरह बेचते हैं, वे किसान से जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा बिजनेस है, वह भी किसान से जुड़ा हुआ है। जितने प्रोडक्ट्स किसान के द्वारा उगाई गई चीजों से बनते हैं, जैसे चिप्स हैं, wheat है, वह इंडस्ट्री भी किसानों से जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि अगर किसान खुशहाल होता है, तो ये सारे लोग खुशहाल होंगे।

शुरू-शुरू में जब अटल जी की सरकार आई थी, उस समय किसान को "किसान क्रेडिट कार्ड" से थोड़ा-सा रिलीफ मिला। उस समय जब किसान साहूकारों से कर्ज लेता था, तब उसको बहुत ब्याज देना पड़ता था और ब्याज के चक्कर में वह किसान मारा जाता था। उस समय "किसान क्रेडिट कार्ड" से किसानों को थोड़ी-सा रिलीफ मिला। किसान के पास एक साधन आया। इसके

माध्यम से किसान अपने छोटे-मोटे खर्च करने में सक्षम हुए, लेकिन इतना sufficient नहीं है। किसान की जमीन कैसी है, उसको सीड कैसा मिलता है, उसको स्प्रे कैसा मिलता है, उसको फर्टीलाइजर कैसा मिलता है, मैं समझता हूँ कि हमें किसान को इन सबके बारे में technically educate करना होगा, किसान को यह बताना होगा। आज भेड़ चाल है, अभी हमारे प्रधान मंत्री जी बता रहे थे कि अगर किसी एक ने देख लिया कि वह लाल डिब्बेवाला स्प्रे लेकर आया है, तो मैं भी यही डालूंगा, लेकिन इससे किसान की जमीन की जो प्रोडिक्टिवटी है, वह कम होनी शुरू हो गई। इसलिए हमारी सरकार ने यह फैसला लिया कि जैसे एक इंसान का हेल्थ कार्ड बनता है, इसी तरह किसान के लिए एक soil health card बनेगा। मुझे खुशी हुई, एक दिन जब मैं अपने माननीय मंत्री जी के पास एक डेलीगेशन को लेकर गया, तो इन्होंने बहुत डिटेल में समझाया कि हमारी सरकार की पॉलिसीज़ क्या हैं। हम बीज बेचने वाले को मिट्टी का एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जब किसान अपना soil health card लेकर दुकानदार के पास आएगा, तब वह यह बताने में सक्षम होगा कि इस तरह की मिट्टी में आपको कौन-सा बीज बोना होगा। अगर वह खाद खरीदने आता है और अगर उसके पास soil health card होगा, तो वह दुकानदार उसको बता सकेगा कि आपको कौन-सी खाद अपनी जमीन में डालनी है। स्प्रे के बारे में भी वह soil health card को देख कर बताएगा कि आपको कौन-सा स्प्रे करना है। आगे मंत्रालय ने जो सोचा है, उसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं, ये किसान तक पहुंचनी चाहिए, नीचे तक जानी चाहिए। इस तरह से वह दुकानदार इतना सक्षम होगा कि अगर किसान soil health card लेकर नहीं आया, तो उसकी दुकान में एक मशीन होगी, वह मशीन उसकी मिट्टी को देख कर बताएगी कि किसान को अब क्या करना है। अगर ये बातें जमीन पर implement होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक किसान को अपनी फसल का पूरा भाव मिलेगा। सर, कई बार बड़ी हैरानी होती है कि अगर एक बिजनेसमैन को एक साल या डेढ़ साल कोई प्रॉफिट नहीं होता, वह लॉस में जाता है, तो वह अपनी दुकान बन्द करके कोई नया बिजनेस शुरू कर लेता है, लेकिन एक किसान ही ऐसा है, जो हर छः महीने लॉस भी झेलता है, फिर भी वह खेती ही करता है। आज खेती एक प्रॉफिटेबल धंधा नहीं रही। आज उसमें हर समय लॉस ही लॉस है और हर फसल पर लॉस होता है, लेकिन फिर भी किसान हिम्मत रखकर उस खेती को करता है। उसके बहुत से फैक्टर्स को अलग-अलग तरीके से बहुत सारे मेम्बर्स ने बताने की कोशिश की है। एम.एस.पी. ठीक होना चाहिए। किसान को उसकी मेहनत का रेट ही नहीं मिलता। सर, एक कैलकुलेशन है, जिसके मुताबिक यह बात सामने आई है कि अगर किसान उसमें अपनी लेबर भी डाल ले तो वह भी उसको नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि उसकी फसल का रेट तय करते समय, कम से कम उसका जो खर्च हुआ है, उसकी जो लेबर लगी है, वह उसको मिलना चाहिए। अगर हम किसान को उसकी लेबर भी नहीं दे पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। कुछ अच्छी-अच्छी योजनाएँ हैं, जैसे— क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, लेकिन अभी तक वह जितनी इम्प्लिमेंट होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो पाई। फार्मर्स की इंश्यारेंस जितनी इम्प्लिमेंट होनी चाहिए थी, वह भी उतनी नहीं हो पाई। मैं यह कहना चाहूँगा कि हम सभी एमपीज़ का भी यह फर्ज बनता है कि हम ऐसा वातावरण बनाएँ, ताकि सरकार की इन सभी स्कीमों को किसानों तक ले जाने के लिए किसानों को ट्रेनिंग मिले और बैंक्स भी किसान-फ्रेंडली हों।

[श्री अविनाश राय खन्ना]

सर, मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूँ। उस समय बहुत दुःख होता है, जब किसान अपनी कैश क्रॉप लेकर मंडी में जाता है और उसको दो रुपये या पाँच रुपये किलो का भाव मिलता है। उस समय वह सोचता है कि इतना तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा हो गया, मेरे ट्रैक्टर का तेल ही इतना लग गया, अगर मैं यहां से दो रुपये भी लेकर गया, तो मुझे ये पैसे लेते हुए शर्म आएगी। वह अपनी बोरी तो बचा लेता है, लेकिन फसल को वहीं छोड़कर चला जाता है। हमें यह सोचना होगा कि कैसे इन फसलों की प्रॉपर मार्केटिंग हो। जब किसान के पास ज्यादा फसल आ जाए, तो उसकी स्टोरेज की इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए कि जब रेट ठीक होगा, तब उसकी फसल बेची जाएगी। उससे किसानों को एनकरेजमेंट मिलेगी, उनको फायदा होगा।

सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक बार मेरे शहर में एक किसान अपनी बंदगोभी, जिसे पत्तागोभी भी कहते हैं, उसको फेंकने लगा, तो अचानक एक कोल्ड स्टोरेज का मालिक वहां पर आया और उससे बोला कि तुम इसे मत फेंको, मुझे दे दो, मैं तुम से पैसे नहीं लूँगा, जब तुम्हारी यह फसल अच्छी तरह से बिक जाएगी, तो मैं तुम्हें उतने पैसे भी दूँगा, उस समय अगर तुम ठीक समझो तो मुझे पैसे दे देना। सर, उस समय उसकी बंदगोभी दो रुपये प्रति किलो बिक रही थी, लेकिन जब शादियों का सीज़न आया तो उस कोल्ड स्टोरेज वाले ने उसी गोभी को 50 रुपये प्रति किलो में बेचा। इस तरह से दो रुपये किलो बिकने वाली वह बंदगोभी 50 रुपये किलो में बिकी। हम समझ सकते हैं कि उससे उस किसान को कितना फायदा हुआ होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके लिए अच्छे कोल्ड स्टोरेज़ की व्यवस्था होनी चाहिए और अच्छी मार्केटिंग के लिए किसानों की मदद करते हुए उनकी प्रॉपर ट्रेनिग होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जब भी किसान के हित में या किसान की बात के लिए कोई फैसला होता है, तो उस समय उस फैसले में किसानियत को जानने वाले प्रतिनिधि शामिल नहीं होते।

(श्री उपसभापति *पीठासीन हुए)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can cooperate with me because we have to pass the Bill also.

श्री अविनाश राय खन्नाः सर, मान लीजिए कोई कमीशन बना, कोई आयोग बना, उसमें किसान का प्रतिनिधि होना बहुत जरूरी है। किसान का ही एक ऐसा इश्यू है, जिसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और न ही यह राजनीति करने वाला इश्यू है। जो मुश्किल है, वह मुश्किल है। इस समय किसान मुसीबत में है और सरकार का यह फर्ज है कि वह किसान को उस मुसीबत से निकाले, ताकि वह अन्नदाता बना रहे, वह अन्नदाता से भिखारी न बने। इसके लिए हम सब भी कोशिश करें। मुझे आशा है कि इस एनडीए गवर्नमेट ने जो-जो स्कीम्स बनाई हैं, वे किसानों तक पहुँच पाएँ, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि मंत्री जी खुद किसान हैं, ये उनकी वेदना समझते हैं और हमारी सरकार भी किसान-हित की सरकार है, वह भी उनकी वेदना समझती है, लेकिन एक collective effort करके हम उस किसान को इस मुसीबत से निकालेंगे, ऐसी मुझे आशा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. We are strict on time, because we have to pass a Bill also. It is already committed.

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhna Pradesh): Sir, you keep saying that we have to pass a Bill. What happened to the Railway Budget debate?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That has been decided.

SHRI JAIRAM RAMESH: This is for the first time this is happening. It has never happened before, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Now, listen. That is all decided in the BAC as to when the Railway Budget is to be taken up. The BAC decided and it has been informed. You should read the bulletins.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, this is a match fixing that is going on. I protest on this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can protest. I have no problem. You have a right to protest.

SHRI JAIRAM RAMESH: You need a debate on the Railway Budget and the General Budget.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. See, there is already a decision taken in the BAC and also in the meeting of the leaders that today we will pass a Bill. This is as per the decision taken by the leaders in the morning in the presence of the hon. Chairman. I cannot deviate from that. You should talk to your leaders who attended the meetings and find out what had happened. You have a right to oppose, I agree. You also have a right to question. But, at the same time, I have a right to reply.

श्री मधुसूदन मिस्त्री (गुजरात): उपसभापति महोदय, मैं आपका शुर्किया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया।

श्री उपसभापतिः मिस्त्री जी, आपका बोलने का टाइम छह मिनट है।

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः सर, ठीक है। मैं खासकर के कृषि मंत्री जी का ध्यान इस देश के आदिवासी इलाकों की ओर, आदिवासी इलाकों में रह रहे किसानों की ओर और ओबीसी किसानों की ओर दिलाना चाहता हूं। देश में करीब 8 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों की बस्ती है और अब शायद वह बढ़ गई होगी तथा यह अब 10-11 करोड़ से कम नहीं होगी। इसी के अंदर ओबीसी के लोग भी रहते हैं। ये सभी किसान हैं, क्योंकि वहां पर बहुत कम इलाकों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। उनके पास में खेती के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता है। वहां पर इरिगेशन की फैसेलिटीज़ नहीं होती हैं। वहां पर जितने भी डैम बने हुए हैं, उनमें पानी भरा हुआ है। माननीय मंत्री जी, आप सुन रहे होंगे, ऐसी मैं आशा रख रहा हूं।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): मैं आपको सुन भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं।

श्री उपसभापतिः ये दोनों कर सकते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः सर, देश के सभी आदिवासी इलाकों के अंदर बड़े-बड़े डैम बने हैं। मेरी खुद की कांस्टिट्युअंसी के अंदर ऐसे-ऐसे इलाके हैं, जहां पर मेरी नज़रों के सामने पानी है, बहुत विशाल सागर है और मेरा मकान वहां से सिर्फ 500 मीटर दूर है, लेकिन मैं उसमें से पानी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मेरा मकान ऊपर की तरफ है, मेरा खेत ऊपर की तरफ है। जो नीचे जमीन है, वह जमीन पथराव वाली होती है। मैं कुआं खोदता हूं, तो नीचे से पत्थर आ जाते हैं। इसमें रास्ते का ठिकाना नहीं है। आज भी ये इलाके दूसरे देशों के इलाकों से बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि दूसरे मैदानी इलाकों की फसल में, जो modernization हुआ है, उससे बहुत पिछड़े हैं। हालांकि आज भी वहां के किसान आर्गेनिक खाद का प्रयोग करते हैं, वे फर्टिलाइजर का बहुत कम यूज करते हैं। आज भी ओरिजनल सीड्स आपको आदिवासी इलाकों के अंदर मिलेंगे, खासकर तुअर के। अगर सरकार चाहे, तो इसको प्रिजर्व कर सकती है, क्योंकि बीज का बहुत जल्दी से नाश हो रहा है। सर, एक तो प्रोडक्शन कम है, इरिगेशन की प्रॉब्लम है, आपने farm pond की योजना चलाई, यह गुजरात के अंदर बहुत चली थी, लेकिन यह योजना आदिवासी इलाकों के अंदर इसलिए नहीं चलती कि नीचे से पत्थर आ जाता है। पानी का स्रोत सूख जाता है, जनवरी-फरवरी में जितने भी स्रोत होते हैं, वे सूख जाते हैं। सवाल यह है कि छोटे और बड़े डैमों में जो पानी भरता है, वह पानी इन आदिवासी किसानों के खेतों के अंदर किस तरह से पहुंचाया जाए। सर, वहां पर फसल बहुत कम होती है, प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है, इसलिए वहां से पलायन होता है। अब होली आ रही है, होली से वहां पर पलायन शुरू हो जाएगा। यहां पर कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया जी बैठे हुए हैं, वे उधर बात कर रहे हैं। उनके इलाके के अंदर से हजारों की संख्या में आदिवासी और ओबीसी ...**(व्यवधान)**...

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (गुजरात)ः सभी गुजरातियों का ध्यान आपकी ओर है।

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः वेसब पलायन करते हैं। अब सवाल यह है कि आप उसमें आय बढ़ाने की बात करते हो, आप 2022 की बात छोड़ दीजिए, लेकिन यह आय कैसे बढ़ेगी? पहले कॉटन का भाव 1,400 रुपये प्रति क्विंटल था, अब उसे 1,400 से घटाकर 700 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। जो किसान कॉटन प्रोड्यूस करते थे उन किसानों की हालत इतनी खराब हो गई कि कोई बेचने को भी तैयार नहीं थे। यदि कम्पलसरी हो, तो ही उसको बेचना पड़ता था, उनकी ऐसी खराब हालत थी। वे लोग ज्यादा दिनों तक उसको रख नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, जब उसके प्राइस बढ़ें, तो वे उसे बेचें। सर, तुअर का भाव इतना बढ़ा, लेकिन किसानों को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। Unfortunate पार्ट तो यह है कि इसके अंदर चना, तुअर और जो पल्सेज़ होती हैं, जब वे पकती हैं, तो व्यापारी लोग बैंकों में से पैसा लेकर, उनको खरीदकर अपने यहां किसान के पास ही रखते हैं। वे उसके प्राइसेज़ बढ़ाते हैं और बाद में उनको बाजार में लाकर बेचते हैं, लेकिन वह वहां है, तो उसको मिलता नहीं है। आज इरिगेशन की बात कर रहे हैं, तो आदिवासी इलाकों के लिए, जहा पर OBC और आदिवासी बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं, वहां पर आपको इरिगेशन की व्यवस्था बहुत बड़े पैमाने पर करनी पड़ेगी। मैदानी इलाकों के लिए जो आपकी सोच है, क्योंकि पानी तो डैम से निकलकर सीधा मैदानों में जाता है, सालों से जाता है। जहां पानी है, वहां का किसान एकदम गरीब है और जहां पानी जाता है, वहां का किसान सबसे ज्यादा मजबूत और धनी हो जाता है। आप यह कैसी disparity क्रिएट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से इसका कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए।

आपने अभी आधार की बात की है, मैं उसका सपोर्ट करता हूं, लेकिन आधार योजना से क्या होगा? मैं पहले खाद खरीदूंगा, आप बाद में मेरे अकाउंट के अंदर पैसा जमा कराओगे। अगर यूरिया के एक बैग की कीमत ढ़ाई सौ रुपए है और अगर मुझे बाजार से यह खरीदना होगा ...**(समय की घंटी)**... तो सबसे पहले साढ़े सात सौ या आठ सौ रुपए मुझे एक बैग के लिए देने पड़ेंगे। अगर मुझे तीन बैग चाहिए, तो मुझे 2,400 रुपए देने होंगे। ....**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः एक ही मिनट है।

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः सर, एक ही मिनट बाकी है। मुझे पहले 2,400 रुपए निकालने पड़ेंगे। यदि मेरे पास 2,400 रुपए होंगे, तभी तो मैं यूरिया के तीन बैग लूंगा। आप बाद में तीन या चार महीने के बाद उसमें पैसा डालोगे। मेरे पास वह पैसा नहीं होगा, तो मुझे किसी से लेना पड़ेगा और उसका ब्याज देना पड़ेगा। यह स्थिति सोसाइटी के अंदर है कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, वह ज्यादा बैग खरीद कर ले जाता है और जिसके पास पैसा नहीं होता है, उसको दो-तीन बैग से ज्यादा नहीं मिलते हैं यह हालत सभी जगह है। सर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं, इसलिए MSP को बढ़ाएं, इरिगेशन की फैसिलिटी को बढ़ाएं। जो स्पूरियस बीज है, जिसको कितनी ही कम्पनियां लेकर आती हैं और बेचती हैं, उनके ऊपर सीड का कोई कानून लागू नहीं होता है।

सर, आज सीड से संबंधित कानून दोनों हाउसेज़ के अंदर पेंडिंग है। सीड का इतना बड़ा व्यापार है, लेकिन आज तक सीड का कानून दोनों हाउसेज़ में से किसी भी हाउस में पास नहीं हुआ। मैं स्टेट का यहां नाम नहीं लूंगा, अभी बता रहा था कि उनकी कम्पनी पर किसानों का पांच-पांच करोड़ रुपया बकाया है और उन्होंने जो बीज दिया था, उस बीज के पैसे अभी तक नहीं मिले। दो-दो, चार-चार साल हो गए, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि या तो आप कम्पनी के साथ एग्रिमेंट करो ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः ओ.के.।

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः सर, मुझे आपसे इतना ही कहना था और मैं आशा करता हूं कि आप सबकी जो स्थिति सुधारने की मंशा है, मेरी उसमें पूरा सपोर्ट है, लेकिन वह मंशा बिल्कुल साफ-सुथरी होनी चाहिए।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र)**:** सर, महाराष्ट्र में और देश में किसानों की जो अवस्था है, वह बेहद दयनीय है। सदन में बार-बार उसके ऊपर चर्चा भी होती है। इस बारे में बाहर भी बोलते हैं और किसानों का आंदोलन भी होता है। हम वहां भी जाकर भाषण करते हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ बातें रखी जाती हैं। किसानों पर आसमान और सरकार, दोनों का कहर टूट पड़ता है। कर्णाटक है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में लगभग एक लाख से भी ज्यादा किसानों ने अब तक आत्महत्याएं कर ली हैं। हम आज भी अपने देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं, यह ठीक नहीं है। आत्महत्या करने वालों की संख्या महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। लास्ट वीक महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट में आंकड़े दिए हैं कि गत एक महीने में 130 किसानों ने आत्महत्या की है और 2015 से अब तक 2,700 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। सरकार ने ये आंकड़े हाई कोर्ट के सामने रखे हैं। ये आंकड़े चिंता का विषय हैं। हमारे देश की जो खेती है, वह खेती हमारे किसानों को भी अनाज नहीं दे रही है। हमारे पेट भरे हैं। जो शहर के लोग हैं

[श्री संजय राउत]

और दूसरे लोग हैं, हमारे पेट भरे हैं, लेकिन किसानों का पेट नहीं भरा है। हमारे देश की यह तस्वीर अच्छी नहीं है। अब खेती फायदे का सौदा नहीं रही। कितनी भी खेती हो, दो एकड़ हो, पचास एकड़ हो या साठ एकड़ हो, कोई फायदा नहीं देती। ऐसा हम महाराष्ट्र में देखते हैं, पूरे देश में देखते हैं। आज पवार साहब यहां नहीं हैं, नहीं तो पवार साहब हमेशा इस पर अपनी फीलिग रखते हैं। एक तरफ हमारी जो मिट्टी है, वह बंजर होती जा रही है, उसका कारण क्या है? इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ इंद्रदेव की नाराजगी खेती और किसानों के लिए बहुत मुश्किल बन गई है। बरसात होती है, नहीं होती है, ओले गिरते हैं आदि की स्थिति रहती है। आज भी महाराष्ट्र में कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है। वहां जो फसल आई है, वह भी नष्ट हो गई है। महाराष्ट्र के कुछ जिले तो ऐसे हैं, जहां आज पीने का पानी तक नहीं है। मैं मराठवाड़ा में लातूर डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं। वहां चालीस दिन में एक बार टैंकर से पानी मिलता है। वे कैसे जिएं? ...**(व्यवधान)**... लातूर में, जहां से दो-दो, तीन-तीन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिले हैं, केंद्रीय मंत्री मिले हैं, वहां से एक विचार आया था कि अगर वहां चालीस दिन में एक दिन पानी मिलेगा तो वहां के लोग कैसे जिएंगे? महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में बीस दिन में पानी आता है, जालना में दस दिन में पानी मिलता है। डिप्टी चेयरमैन सर, अगर हमारे देश की यह हालत है, तो इस देश के किसानों के ऊपर हम सिर्फ चर्चा ही करते रहेंगे। किसान और खेती की हालत के बारे में हम आज से नहीं, बल्कि स्वतंतत्रा पूर्व से चर्चा करते रहे हैं। जब स्वतंत्र नहीं थे, तब से हम किसानों की हालत के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। इस देश में किसानों के जो सबसे बड़े नेता रहे हैं लाला लाजपत राय जी, जो प्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्होंने 1928 में सेंट्रल असेम्बली में किसानों की भुखमरी पर भाषण दिया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या बढ़ रही है, अनाजों का उत्पादन बढ़ रहा है, फिर भी लोग और किसान आज भी भुखमरी के शिकार हैं। यह 1928 की बात है। आज हम स्वतंत्र हो गए, हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमारी इकॉनॉमी भी स्ट्रांग हो गई, हम सुपर पावर बनाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश की आज भी वही स्थिति है, जो सौ साल पहले थी। सरकारें बार-बार बदल गईं, लेकिन किसान वहीं का वहीं है। वह पहले भुखमरी से मरता था, आज आत्महत्या करने वाला स्वाभिमानी किसान बन गया है। आज वह दुस्साहस करता है, वह स्वाभिमान के लिए आत्महत्या करता है। हमारे देश में बड़े-बड़े उद्योगपति बैंक को दस-दस हजार करोड़ का चूना लगाकर भाग जाते हैं ...**(व्यवधान)**... वही तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमारा किसान, यदि उस पर बैंक का पांच हजार रुपये का कर्ज भी होता है और वह उसे अदा नहीं कर पाता है, तो आत्महत्या कर लेता है। जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने बताया, बुंदेलखंड के किसान अपना खून बेचकर जी रहे हैं। के. सी. त्यागी जी, आपने कहा कि वे घास की रोटी खाने के लिए मजबूर हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में क्या हो रहा है? साहूकार से कर्ज लेने वाला जो किसान है, यदि वह उसका कर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, तो साहूकार उसकी किडनी निकालकर, बेचकर अपना पैसा वसूल कर रहा है ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)... Shri Sanjay Raut, time is over. ...(*Interruptions*)... Shri Sanjay Raut, your time is over. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय राउतः यह हमारे महाराष्ट्र की ...**(व्यवधान)**... सर देखिए अभी तक पांच मिनट नहीं हुए हैं, एक मिनट की बात है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी विदर्भ गए थे। उन्होंने बहुत

बड़ा टूर किया, किसानों की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की। उनकी क्या मांग थी? राहुल गांधी जी की संपूर्ण कर्ज मुक्ति की मांग थी। किसानों के माल का योग्य दाम मिलने की बात श्री राहुल गांधी जी ने कही है। लेकिन महाराष्ट्र में और केंद्र में, जब आपकी सरकार थी, तब ये सब चीज़ें आपने क्यों नहीं कीं? संपूर्ण कर्ज़ मुक्ति की बात ...**(व्यवधान)**... शिव सेना ने हमेशा संपूर्ण कर्ज़ मुक्ति की बात कही है ...**(व्यवधान)**... वह बात उद्धव ठाकरे साहब ने की है। ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): आप क्या बात करते हैं? ...**(व्यवधान)**... हमारे प्राइम मिनिस्टर विदर्भ गए थे। ...**(व्यवधान)**... आप उसके मालूमात नहीं कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Shri Husain Dalwai, please sit down. ...(*Interruptions*)... Shri Husain Dalwai. ...(*Interruptions*)... Shri Sanjay Raut, address me. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय राउत: विदर्भ में ...**(व्यवधान)**... जिस कलावती के घर में राहुल गांधी गए थे, आज उसके घर का चूल्हा भी नहीं जल रहा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, your time is over. Now, please conclude. ...(*Interruptions*)... Mr. Sanjay, please conclude.

श्री संजय राउत: यह हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे यह जिम्मेदारी सरकार की है, वैसे ही यह हम सब राजनीतिक दलों की भी है। हमने वहां शिव सेना की तरफ से हर जिले में ...**(व्यवधान)**... हमें तो किसानों की ...**(व्यवधान)**... चिंता है। उसकी बेटी की शादी नहीं होती है। हमने जिलों-जिलों में सामूहिक विवाह भी करवाए हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; Mr. K. C. Tyagi, don't create problem. Mr. Sanjay, your time is over. Okay, it is seven minutes. Sit down; sit down. Nothing more goes on record. Nothing more goes on record. Now, Shrimati Viplove Thakur. ...(*Interruptions*)... Shrimati Viplove Thakur.

श्री संजय राउत : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mistry, you have no time. Only for Shrimati Viplove Thakur, please. Shrimati Viplove Thakur.

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सर, मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए, मुझे एक सजेशन देना है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mistryji, no. ...(*Interruptions*)... Mistryji, please sit down. Mistryji, please sit down. Shrimati Viplove Thakur, you start, please.

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। यहां आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। यह एक ऐसा विषय है, जो सबको छूता है, जो सबसे जुड़ा हुआ है। हम अनाज के बिना नहीं रह सकते, हम खाने के बिना नहीं रह सकते। हमें अनाज चाहिए, चाहे गेहूँ हो,

* Not recorded.

[श्रीमती विप्लव ठाकुर]

6.00 P.M.

चाहे चावल हो, चाहे बाजरा हो, चाहे जौ हो, चाहे मक्की हो। इनको कौन बोता है, इनको कौन रोपता है? वह है किसान, जिसका दर्द यहां पर बताया जा रहा है, जिसे समझने की जरूरत है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि जिन किसानों ने आत्महत्या की है, क्या उनका कोई सर्वे किया गया है कि वे किस category को belong करते थे, उन्होंने आत्महत्या क्यों की, क्या reasons थे? पंजाब में जो आत्महत्याएँ हो रही हैं, जिसकी अभी अविनाश जी ने भी बात की है, क्या आपने उसके पीछे जाकर देखा है कि वे आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर हुए? मैंने आपसे पहले भी एक supplementary question पूछा था, जिसका आप ठीक तरह से जवाब नहीं दे सके कि यह जो छोटा किसान है, जिसके पास दो-दो एकड़, तीन-तीन एकड़ जमीन है, वह बड़े-बड़े किसानों से, बड़े-बड़े जमींदारों से लीज़ पर खेत लेता है, जमीन लेता है, जिसमें वह इस आस से बीज बोता है कि इससे इनकम होगी, क्योंकि उसके छोटे खेतों की फसल से इतना लाभ नहीं हो सकता है। वह सोचता है कि अगर मैं ज्यादा जमीन में बोऊँगा, तो मुझे लाभ होगा, लेकिन उस किसान को न तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी मिलती है, न बीज के लिए कोई सहायता मिलती है। उस किसान को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं दी जाती है, जो बड़े-बड़े जमींदारों से लीज़ पर जमीन लेता है। इसलिए वह मजबूर होकर साहूकार का दरवाजा खटखटाता है, जहां से वह पैसा लेता है। वह फसल बारिश की वजह से, सूखे की वजह से खराब हो जाती है। मंत्री जी, ये तो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, लेकिन जो हमने पैदा की हैं, आज बंदरों की वजह से, आज नीलगाय की वजह से, आज सूअर की वजह से जो खेती खराब होती है, उसका compensation कौन देता है? उस किसान की भरपाई कैसे होगी, इसका समाधान कहीं नहीं किया गया है। यह भी सोचने की बात है। आज हमारे हिमाचल प्रदेश में किसानों ने जमीन बीजनी बंद कर दी है, क्योंकि सूअरों, बंदरों और नीलगाओं ने फसलों की फसलों खत्म कर दी हैं, खेत वीरान पड़े हुए हैं, वहां खेती नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर जानवरों का इतना आतंक है। क्या आपने इसके बारे में कोई समाधान सोचा है? क्या आपने इसके लिए भी कोई उपाय किया है, जिससे उस खेती को बचाया जा सके? उस किसान के लिए कोई समाधान नहीं है।

कल जेटली जी कह रहे थे कि बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स इसलिए पैसा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनकी goods नहीं बिकती हैं, उनका व्यापार नहीं हो पाता है, इसलिए उनका NPA माफ किया जा रहा है। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि छोटे किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ किया जाता? आज माल्या जी इस देश को छोड़ कर चले गए हैं, आपकी सरकार क्या कर सकी? चूँकि वे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वे इस भूमि को छोड़ कर जा सकते हैं, लेकिन छोटा किसान कहां जाएगा? वह अपनी धरती मां को छोड़कर कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है, सबके पास केवल बातें ही बातें हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप उन किसानों के लिए सोचिए, उनका बीमा कीजिए, उनकी फसल के ऊपर ध्यान दीजिए कि किस तरह से वे अपने खेतों को बचा पाएं और कैसे उनको सब्सिडी मिल सके।

बड़े-बड़े लोगों को तो सब्सिडी दी जा रही है, उनका बीमा भी हो रहा है, उनके लिए बड़ी-बड़ी स्कीम्स बन रही हैं, लेकिन जो किसान है, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। पहले यह होता था कि बड़े-बड़े ज़मींदारों ने टेनेंट्स रखे हुए थे, जो बीज बोते थे। फसल आने पर आधी फसल उनको मिल जाती थी और आधी वे जमींदार रख लेते थे, लेकिन आज धीरे-धीरे वह प्रथा खत्म

हो रही है, क्योंकि आज लीज़ की प्रथा आ रही है। यह काम सबसे ज्यादा पंजाब में हो रहा है, जो आज किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है। किसान अपने बच्चों से बिछड़ने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि वह उस साहूकार को फेस नहीं कर पाता है, जिससे उसने पैसा लिया होता है। पैसा न दे पाने के कारण उसकी कुर्की होने लगती है और उस कुर्की से, उस शर्मिन्दगी से डर कर वह आत्महत्या कर लेता है। उसको क्या दिया जा रहा है?

मंत्री जी, किसान की यह जो पीड़ा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको जानिए। केवल फाइलों के बीच में रह कर काम नहीं बनेगा, आप प्रेक्टिकली जाकर इसे देखिए कि क्यों वह किसान आत्महत्या कर रहा है? क्यों वह इतना ज्यादा पिस रहा है? आपको इसे देखना ही पड़ेगा।

श्री राधा मोहन सिंहः मैं आपकी बात को नोट कर रहा हूं।

श्रीमती विप्लव ठाकुरः लिखने से कुछ नहीं होगा। आप किसानों के उन बच्चों से जाकर मिलिए, उनकी फैमिलीज़ से मिलिए और उनका दर्द समझिए। आज उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, आगे आप जवाब देते रहिएगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको उनकी तरफ ध्यान देना होगा। उनके लिए आपको स्कीम्स बनानी पड़ेंगी, उनको राहत देनी पड़ेगी, उनको सब्सिडीज़ देनी पड़ेगी। यह जो साहूकारों की प्रथा है, इसको रोकने के लिए प्रयास कीजिए। आज हर गांव में बैंक हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, जो गांव के अन्दर हैं और जो पंचायतों के अंतर्गत आते हैं। आप उन बैंकों को पैसा दीजिए, ताकि वे किसानों की मदद कर सकें। किसान कम इंटरेस्ट पर उनसे पैसा ले सके और अपनी खेती कर सके। खेती के लिए वह बीज ले सके, खाद ले सके। ठीक है, आपने धरती की जांच के लिए सुविधा दे दी है, जैसा अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि ज़मीन की जांच के लिए हेल्थ कार्ड बनेगा और दुकानदार उसकी जमीन को देखकर यह बताएगा कि कौन सा बीज लेना है, कौन सा नहीं लेना है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude. ...(*Interruptions*)... Please conclude. ...(*Interruptions*)... Okay. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः मैं आपसे यही कहूंगी कि इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। आप इस पर सीरियसली सोचिए और ध्यान से देखिए कि आज हमारा अन्नदाता क्यों मर रहा है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः आप उसकी पीड़ा को समझ कर उसका समाधान कीजिए, तभी यह सरकार आगे चल सकेगी, नहीं तो नहीं चल सकेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, I am going to associate myself with a lot of what my hon. colleagues have said. So, I do not want to repeat myself. मैं समझती हूं सबसे पहले हम बुनियादी बात पर आ जाएं। हम सब बार-बार इस हाउस में किसानों के लिए हाय-हाय करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। चन्द महीनों में दोबारा हम फिर ऐसे ही बोलते रहेंगे। अगर सरकार बहरी, गूंगी और अंधी बनकर बैठेगी, तो किसान की पुकार यहां तक पहुंचेगी ही नहीं। सबसे पहले तो आप इस हाउस में Seed Bill को

[Shrimati Renuka Chowdhury]

लेकर आइए। जब तक Seed Bill को लाकर आप seed monitoring नहीं करेंगे, तब तक किसान की व्यवस्था होना कठिन है।

Second thing, the seed failure has not been covered by the 'crop insurance'. अकाल आएगा, बाढ़ आएगी, ओले पड़ेंगे, तब उसको बीमा मिलेगा, यह कहां की बात है? अगर बीज खरीदकर हम बोएंगे और वह अंकुरित होगा ही नहीं, तो उसको कम्पंसेशन कौन देगा?

श्री राधा मोहन सिंहः सर, एक मिनट, शायद मैडम ने ठीक से इसे पढ़ा नहीं है। जब हम जवाब देंगे, तब उसमें तो हम यह बताएंगे ही।

श्रीमती रेणुका चौधरीः आपके crop insurance में seed failure is not covered.

श्री राधा मोहन सिंहः यह कवर्ड है। यदि बुआई नहीं भी हुई होगी, तो भी उसका बीमा होगा और बुआई के बाद यदि आपदा में वह नष्ट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा बीमा होगा। हम बाद में इसका जवाब डिटेल में देंगे।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Seed failure is not covered by the 'crop insurance'. आप इसको जोड़ दीजिए, बस इतनी ही बात कहना चाहती हूं। हम कौन सा आपसे लड़ रहे हैं? हम तो आपके साथ मिलकर किसानों की मदद के लिए ही खड़े हैं।

तीसरा, सब लोग MSP की बात करते हैं। ठीक बात है, लेकिन MSP में होता क्या है कि आधे एकड़ का किसान भी मिर्ची बोएगा और 100 एकड़ का किसान भी मिर्ची बोएगा और हम MSP के आधार पर ही जीते रहेंगे। You have to have a concentrated approach. कि 0 to 2 acres and 0 to 5 acres के लिए, small and tiny farmers के लिए आपको क्रॉप प्लांनिग ऑफ वैल्यू एडिशन क्रॉप देना चाहिए। उसके तुरन्त बाद post-harvest technologies have to be put in place. इज़राइल जैसे देश में 40 साल से वे लोग वैल्यू एडिशन करके irradiation का खाना बेचते हैं। Irradiation is not to be confused with normal radiation; irradiation is a highly-sterilising process, जिसकी वजह से इजराइल में they advertise that irradiated *dana* or irradiated meat means it is value addition. किसान को 40 परसेंट ज्यादा रेट मिलता है, ताकि वह उसको irradiate करे। BARC, Mumbai, gives us irradiation technologies. हम अगर ये टेक्नोलॉजीज़ इन इलाकों में स्थापित कर देंगे, तो one district can service three, four districts together. आपकी फूड सिक्योरिटी भी उसमें बढ़ जाएगी, ब्याज की कमी, टमाटर का नुकसान यह सब नहीं होगा। उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी and you will be able to support the farmers. फार्मर को सपोर्ट प्राइस मिल जाती है।

चौथी बात, आपको क्रॉप प्लांनिग करनी चाहिए। You can't say that स्टेट देख लेगी, फलां देख लेगा या वह देख लेगा। खाना तो वे सबको खिलाते हैं। चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक और राष्ट्रपति तक किसान ही खाना खिलाता है। भिखमंगे बन कर घूमने की उसकी यह परिस्थिति ठीक नहीं है। वह अपने परिवार को बचाने के लिए शहीद बन जाता है, क्योंकि ऐसी ढीठ सरकार बैठी है, जो यह समझती नहीं है। इस बजट में आपने उन लोगों का क्या मजाक उड़ाया है? दुनिया को दिखाने के लिए, चंद मिनटों के लिए हाउस में खड़े होकर कह दिया कि

बजट बढ़ गया। कहां बढ़ गया? It has increased from 0.17 per cent of the GDP to 0.19 per cent. यह तो मजाक ही उड़ाया है। हमारे घाव पर आप लोगों ने एक और पत्थर डाल है। यह दिखाने के लिए बड़े सयानेपन से हमने कहा कि हम वहां से यहां ले आए, फीगर्स और दिखा दिए, सबने मेज थपथपायी और तालियां बजा दीं। क्या मिला हमारे किसान को? तेलंगाना में हजारों लोग मर गए। आप बताइए कि जो कौलदार किसान है, जिसके पास जमीन नहीं है, वह कौल पर ऑनर से जमीन लेता है, उसकी क्रॉप फेल होती है, तो कम्पेंसेशन लैंड ऑनर को मिलती है, कौलदार को कुछ नहीं मिलता है। तो आत्महत्या के सिवाए उसके पास और क्या चारा है?

इंदिरा गांधी जी ने बैंक्स को नेशनलाइज्ड इसीलिए किया था कि वे मनी लेंडर्स के चंगुल से निकलें और बैंक में अधिकार से जाकर हक़ से पूछें। आज के दिन सभी लोगों ने जो कहा, बहुत बड़े-बड़े बिजनेस वालों को तो छूट मिल जाती है और हमारे घरों में जाकर बैंक वाले, जब गरीबी में और कुछ बचा नहीं है, तो हमारे घर की चौखट उखाड़ कर ले जाते हैं। यह शर्म हम सह नहीं सकते हैं। आप जानते नहीं कि दक्षिण में कितना आत्मगौरव रहता है। बीवी का मंगलसूत्र बगल के गांव में हम गिरवी रख कर पैसे उधार लेते हैं, क्योंकि किसान का हाथ कभी ऐसे नहीं बढ़ा, उसने यूँ ही दिया है। तो इसीलिए you have to take concerted efforts. Think out of the box. आपके सामने देश में malnutrition खड़ी है, तो अगर पोष्टिक आहार के लिए आपको जाना है, तो you have to grow pulses and millets. Identify your districts for growing cereals and pulses. Incentivise those districts to grow that. हम पर्यावरण या environment के बारे में बोलते रहते हैं, तो आपको the impact on farmers' crop planning देखना चाहिए। कहीं एक इंडस्ट्री आकर कह देती है कि जहां हम सोना उगाते हैं, वह बंजर बन जाती है, तो युक्लिप्टस ट्रीज़ लगा दो। You have to guide the farmers कि युक्लिप्टस लगाने से तीन क्रॉप्स के बाद वहां आप ईंट के भट्ठे ही लगा सकते हैं, और कुछ नहीं उगा सकते हैं। Why are you not guiding the farmers on crop planning? सॉयल हेल्थ कार्ड लेकर वे क्या करेंगे? क्या वे हॉस्पिटल पहुँचेंगे? सॉयल हेल्थ कार्ड लेकर उसको समझाना है कि what is the intermediary crop? Intermediary crop is to recharge the soil. उसके बीज की अवेलेबिलिटी तुरन्त होनी चाहिए। They can ensure seed availability, timely intervention, time-to-time inputs on crop and they can make available post-harvest technologies to keep it sustainable and incentivise the districts to grow what is in shortage in India. अब इतनी हेक्टेयर जमीन have changed from food crop to cash crops. क्या हमेशा देश के बारे में सोचने और देशभक्ति स्थापित करने के लिए किसान की ही जिम्मेदारी बनती है, क्या बाकी लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? Nobody thinks that the farmer की क्या हालत होती है, लड़की जवान हो जाती है, शादी-विवाह में आज के दिन कोई आता नहीं है, बीस-बीस एकड़ के किसान का भी कोई चारा नहीं है। हमारे बच्चे किसान नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि it is not a sustainable livelihood. ...(*Time-bell rings*)... हेंडीक्राफ्ट्स का सामान बेचते हैं तो **...(समय की घंटी)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Renukaji, time is over.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: This goes to sustaining our ...(*Time-bell rings*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Renujkaji, time is over.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I am concluding. ...(*Time-bell rings*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Renukaji, time is over, please.

श्रीमती रेणुका चौधरीः महिला किसानों के लिए — Sir, I am concluding; I am concluding — you have to have a design change in farming instruments. सिवाए John Deere जो दो गियर के ट्रेक्टर हैं, बाकी ट्रेक्टर के लिए हमें लिबास बदलना पड़ता है। We are not able to drive the tractors. बाकी जो लोअर शिफ्ट गियर होते हैं, उन्हें साड़ी पहनकर चलाने में दिक्कत होती है। You have to change the instruments. You have to change the premise of agricultural farming. You must understand that you will face a national food calamity if you don't protect the producer of this country. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Majeed Memon. Mr. Majeed Memon, your party has only four minutes. So, you have to conclude in four minutes.

SHRI MAJEED MEMON (Maharashtra): Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will thank you for concluding in four minutes.

श्री माजीद मेमनः सर, बहुत सी बातें हुई हैं और किसी ने, हमारे एक सदस्य ने यह बात भी कही कि पूर्व प्रधान मंत्री ने एक नारा दिया था, "जय जवान, जय किसान" उसकी महत्ता क्या है? जवानों को जो हम आज आदर देते हैं, जवानों को जो आज हम शहीद का रुतबा देते हैं, जवान को जो हम सेल्यूट करते हैं, उसी सेल्यूट, उसी आदर, उसी रुतबे का हकदार आज भारत का किसान भी है। पहले हम यह नोट कर लें कि भारत के किसान को हम किस तरह ट्रीट करते हैं, मेरे बहुत सारे साथी सदस्यों ने यह बात कृषि मंत्री जी के सामने रखी है। मेरी उनसे अपील सिर्फ दो बातों पर है। एक तो यह सुइसाइड वाला जो मामला है कि लाख के करीब किसानों ने अपनी जान दे दी, मैं कहूंगा कि वे सारे शहीद हो गए। इसलिए कि हमारा सिस्टम फेल हुआ, हमारी सरकारें फेल हुई, हम उनकी जानों को नहीं बचा सके, उन्हें नागरिकता का जो अधिकार है हम उनको रोजी-रोटी, मुहैया नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। मुझे तो दुख इस बात का है कि हमने यहां तक पढ़ा कि डिस्ट्रेस में किसान ने मुख्यमंत्री से आत्महत्या करने की अनुमति मांगी। अब आप बताइए कि इससे बड़ा इंसल्ट क्या हो सकता है? यह जो आत्म हत्याएं होती हैं उसके पीछे सबसे बड़ा मूल कारण कर्ज है। मैं इस समय केवल महाराष्ट्र की बात करुंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। महाराष्ट्र में जो सुइसाइड हुए हैं, उसमें 99 परसेंट सुइसाइड्स के बारे में आप स्टडी करें, उसका बैकग्राउंड निकालें, तो वे सारे कर्ज़ की वजह से हुए हैं और कर्ज़ का मामला ऐसा है कि हमारा जो सिस्टम है वह इस बात का ध्यान नहीं रखता कि किस तरह से किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। जो पैसे उन्हें दिए जाते हैं, बैंक के मुताबिक उससे दस गुना ज्यादा इंटरस्ट पर साहूकार उन्हें पैसा देता है और खड़ा हो जाता है कि अगर वह पैसे वापस नहीं किए तो उनके घर के बर्तन लेकर चला जाएगा। तो इन परिस्थितियों में किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है। बैंकों के नाम से आप जो पॉलिसी बनाते हैं, क्या वह एक गरीब किसान तक पहुंचती है? बैंकों में जो लोन देने का प्रोसीजर है, वह इतना लम्बा-चौड़ा है कि जरूरत आज है और पैसा अगर आप छः महीने बाद पास करेंगे या उसको मजबूर करेंगे कि वह बैंक में दौड़ता रहे, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। फिर क्यों नहीं किसानों

को बैंक से कर्जा देना या किसानों की मदद करना, उसके लिए स्पेशल चैनल बनाया जाए। आप उसको एक साधारण कस्टमर से हटकर Kisan should be considered as a special case और किसानों की सुविधा और किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए आपको यह करना बहुत आवश्यक है। किसानों को बहुत सारी सब्सिडी दी जा सकती है। किसानों को डीजल में सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती? किसानों को और सुविधाएं क्यों नहीं दी जा सकतीं? अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश के किसान अपना यह पीढ़ियों से चला हुआ पेशा छोड़ दें, आज केरल में तमाम किसान यह कहते हैं, महाराष्ट्र में किसान यह कहते हैं कि हम अपने बेटे को खेती बाड़ी में नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, पेट नहीं भर सकता। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा agrarian revolution है और जो देश की विशाल परम्परा रही है कि यह एक agricultural country है, जहां primary occupation जो है, वह agriculture है। अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों को 'Make in India' कहकर इण्डस्ट्री बनाने की बातें करने की प्राथिमकता कहां रही? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि हम किसानों की आत्महत्याओं को रोकें। मैं चाहूंगा कि माननीय कृषि मंत्री जी कृपा करके इसको देखें। महाराष्ट्र में, जहां से मैं आता हूँ, जितनी आत्महत्याएं हुई हैं, उन सारे केसेज़ की स्टडी करें कि वे क्यों हुई हैं और उनको रोकने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? जब तक हम यह पहला काम नहीं करेंगे, उनकी आत्महत्याओं को नहीं रोकेंगे, उनकी आत्महत्याओं के कारण को जान कर उसको solve करने का रास्ता नहीं निकालेंगे, तब तक यह अनरेस्ट बना बनेगा, तब तक हम कोई agrarian promotion नहीं कर सकते। यह agrarian crisis, जिस पर पूरे वर्ल्ड की नजर लगी हुई है कि भारत जैसे विशाल देश में agrarian crisis के कारण क्या हैं? वैसे agrarian crisis के जो fundamentally दो-चार कारण हैं, उनमें एक है liberal import of agricultural products. Number two, cut-back in agricultural subsidies. Number three, decline in Government investment in the agricultural sector. Number four, restructuring of the Public Distribution System. And number five, Special Economic Zones. ...**(समय की घंटी)**...I Broadly analyse करने के बाद ये सारे कारण सामने आए हैं, जिसकी वजह से we are facing agrarian crisis today. The duty of the Agriculture Minister would be to examine all this...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)... All right. It's over.

SHRI MAJEED MENON: ...and take curative measures as early as possible.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri K. P. Ramalingam. I think you would speak in Tamil.

SHRI K. P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Thank you, Sir. In the 'Others' category, there are only three. So, you can give me ten minutes. I would like to speak in Tamil, Sir.

*Hon'ble Deputy Chairman Sir, I have got the opportunity for the fourth time in this august House to speak about agrarian crisis. Saint Thiruvalluvar, poet of our land, has said,

---

* English translation of the original speech made in Tamil.

[Shri K. P. Ramalingam]

'Who ploughing eat their food, they truly live

The rest to others bend subservient, eating what they give'.

That is, they alone live who live by agriculture, all others lead a crininging dependent life. He had written this couplet two thousand years ago.

'Who ploughing eat their food, they truly live

The rest to others bend subservient, eating what they give'.

But today, neither the Prime Minister of India nor the Minister of Agriculture protects the farmers. In reality, the Minister of Road Transport and Highways is protecting the farmers. How is it possible? He has laid four-lane roads near agricultural land as a result of which land price has increased. Farmers sell 2-3 acres of their land to earn their livelihood. That is how, he protects farmers. I am in a position to point out this fact to the entire nation.

Indian economic structure and India's integrity are protected due to the sacrifice of farmers. Neither the corporates nor the industrialists nor the Union Government nor the State Governments protect the economic structure and integrity of India. It is the farmers who are protecting India's integrity and its economy. There is no place for religion, caste or gender in their labour.

So many industries had flourished in India during the past. The industries which flourished in sixties diminished in eighties. The industries which flourished in eighties diminished in 2000. But agriculture is the only profession which has survived for thousands of years. Though the agricultural sector in India has suffered so many trials and tribulations, our farmers have protected their profession. They have protected agriculture throughout their life even though they had suffered painfully. Though the profession of agriculture is not diminished, farmers are suffering. There is a threat to agriculture due to lack of proper income to farmers.

All bureaucrats and all politicians are children of farmers. After coming to Delhi, they do not worry about the farmers. After becoming urbanites, they forget the sufferings of rural people. They do not worry about the farmers. How are farmers viewed? We speak so high of them. But they are treated as slaves. They are considered merely as food producers. Only the incumbent Finance Minister has said that agriculture is an income generating sector. I appreciate him for presenting this budget. The Union Government have impressed farmers in their speeches. Whether they will implement their words, has to be seen in future. In today's reply, the Prime Minister did not mention anything specific about farmers.

Indian agriculture is severely affected due to many factors such as improper water management, natural disasters and absence of proper price that commensurates with production cost. How can water management be performed properly? All rivers have to be interlinked. At least, the rivers in States have to be interlinked. Then proper water management is possible. All rivers have to be interlinked. All water bodies including irrigation canals, ponds and lakes have to be protected. All encroachments on water bodies, irrigation canals etc. have to be removed. Besides, they have to be properly maintained annually. Care has to be taken so that plastic pollutants are not dumped in water bodies. So far, no Government has undertaken this responsibility.

There are many factors which affect the price of agricultural products. Whatever subsidy is given, it is not reaching the targeted farmers. Only 10% of the allocated subsidy reaches the farmers. 90% of the subsidy rests with the Government machinery itself. All subsidies have to be given to the farmers by way of cash transfer. For example, if a sugarcane farmer is to be paid ₹ 200 per tonne, ₹ 2000 per 10 tonnes has to be paid to him by way of direct cash transfer. How can the situation be improved? Subsidy has to be allocated separately for agricultural products. Separate subsidy per acre if the land is of paddy cultivation, separate subsidy for sugarcane, separate subsidy for cereals and separate subsidy for vegetables have to be given. That is, subsidy has to be given to the farmers on the basis of their production.

The Union Government is encouraging organic farming by means of so many advertisements. But in organic farming, farmers may suffer due to income loss. I can quote certain examples from the past. Whether it is possible to earn income through organic farming is to be seen. Can a farmer get fertilizer or manure under organic farming? It is like placing a camphor in the midst of a line of fire. How can we protect the camphor if it is placed in the midst of a line of fire? How can we protect a farmer who owns less than 5 acres of land if he practices organic farming.

Some years ago, a practice named Green farming came into existence for production of flowers and vegetables. But nowadays these green farms are facing a severe crisis due to strong wind. Green farms are diminishing. Farmers are unable to repay their loans. Green farming farmers in Krishnagiri, Hosur districts of Tamil nadu face severe financial crisis. Insurance companies refuse to pay insurance for the loss. So farmers are unable to pay their loans.

Today you are saying that all farmers will be covered under insurance schemes. How are you going to implement it? How is it possible? You have to take survey about it in every panchayat, in every zone and in every district. You have to analyse the situation at the grass root level. If you do not take such efforts, you will land in quicksand instead of achieving your target.

[Shri K. P. Ramalingam]

If you want to protect the economy of this country, you have to protect the farmers. Don't listen to the bureaucrats. Please form committees having Members of Parliament as its members. Please listen to the advice of Members of Parliament, because they are with the farmers at the grass root level. Please lend your ears to us and accept our suggestions. Don't listen to the advice of bureaucrats in formulation of schemes. With these words, I conclude my speech. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, discussion is over. Hon. Minister, are you replying today or later?

श्री राधा मोहन सिंहः उपसभापति महोदय, इतने सारे सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, ऐसा लगता है कि मुझे एक-डेढ़ घंटे का समय चाहिए। मुझे इसके लिए ज्यादा समय चाहिए, चाहे जितनी देर तक भी सदन बैठे। दूसरी बात यह है कि इस विषय को प्रमोद तिवारी जी ने शुरू किया था। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात रखी है और मुझे ज्योतिषी के यहां जाने की सलाह दी है। मुझे लगता है कि वह खुद ज्योतिषी के यहां चले गए हैं। उनके लौटने की प्रतीक्षा करें और मुझे समय भी मिले।

श्री उपसभापतिः आप सबके सजेशन की रिप्लाई देना।

श्री के. सी. त्यागी (बिहार)**:** सर, पिछली बार भी, जब रूरल डिस्ट्रेस पर डिबेट हुई थी, तो माननीय मंत्री जी को याद होगा कि मैंने डिबेट को इनिशिएट किया था। शोर-शराबे में उस दिन सदन नहीं चला, हमारे पिछली बार के जो ग्रीवेंसेज़ हैं, जो एड्रेसिज़ हैं, जो हमने मंत्री जी को नोट कराए थे, उनके बारे में, मेरा मंत्री जी से अनुरोध होगा। ...**(व्यवधान)**... पिछली बार चार घंटा ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः चलो चार घंटा। ...**(व्यवधान)**...

श्री के. सी. त्यागीः इसको गांव की भाषा में ब्याज समेत कहते हैं। यह मेरे स्वभाव में ही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः त्यागी जी, आपके सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मंत्री जी जवाब देंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the National Waterways Bill, 2015.